सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 361, नई दिल्ली । रविवार, 10 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते।

03 दक्षिणी दिल्ली सीट पर रहा है गुर्जर मतदाताओं का वर्चस्व
06 बॉन्ड बंद होने से चुनावों में बढ़ेगा काला धन
08 पीएम मोदी वाराणसी में करेंगे 28 किलोमीटर लंबा रोड शो....

18 किमी. तक का रोड शो करेंगे पीएम मोदी, होगी 40 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था; एसपीजी ने किया दौरा....

संजय बाटला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए वह 18 किमी की दूरी कार के काफिले से करेंगे। उसके बाद वह रैली स्थल पर पहुंचेगे। रैली स्थल के पीछे बन रहे हेलीपैड पर खड़े हेलीकॉप्टर से उनकी वापसी होगी। एसपीजी एआईजी के नेतृत्व में एक टीम शुक्रवार को मौके पर पहुंची। जिसने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पूरे स्थल का निरीक्षण किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुग्राम में 11 मार्च को प्रस्तावित दौरे को लेकर एसपीजी के एआईजी ने अपनी टीम के साथ रैली स्थल का दौरा किया। जहां पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव व अन्य अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक के दौरान बजघेड़ा बॉर्डर से रैली स्थल तक प्रधानमंत्री के काफिला कार से आने की बात तय हुई। रैली को संबोधित करने के बाद उनकी वापसी हेलीकॉप्टर से होगी। मंच से करीब 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही हेलीपैड बन रहा है। जहां से उनकी वापसी होगी।

कार्यक्रम सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप में भव्य तरीके के किया जा सके इसे लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव व पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने आयोजन स्थल पर ही जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बिंदुवार की जाने वाली तैयारियों के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, रूट लाइन की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्वों का निर्वहन करने से संबंधित निर्देश दिए। एसपीजी की टीम रैली स्थल पर दूसरी बार पहुंची थी। करीब डेढ़ घंटे तक प्रधानमंत्री गुरुग्राम की सीमा में रहेंगे।

बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्य दायित्वों की चर्चा कर चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल, भोजन, वाहन, विद्युत, बैठने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को उचित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर लगाए जाने वाली प्रदर्शनी, हेल्प डेस्क एवं इसके उचित प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए।

सीपी द्वारा उचित ट्रैफिक व्यवस्था, रूट लाइन एवं विधि व्यवस्था से संबंधित सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित, सुरक्षित और शांतिपूर्ण रूप में भव्य तरीके के किया जा सके इसे लेकर प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था संपन्न करें। प्रशासन की ओर से 40 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।

गंगा के आर-पार दौड़ेगी सपनों की ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण- लोगों को मिलेगा यह बड़ा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा सोनवल से सिटी 9 .600 व सोनवल से घाट की ओर जाने वाली 7 .156 किमी लंबी दोनों नई रेल लाइन का लोकार्पण से पूर्व शनिवार को लाइट गुड्स ट्रेन के जरिए अंतिम और फाइनल ट्रायल किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा। लाइट गुड्स ट्रेन दोनों नई रेल लाइनों एवं नवनिर्मित रेल पुल पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से साढे.पांच मिनट में पहुंची।

गाजीपुर : सोनवल से गाजीपुर सिटी और घाट स्टेशन तक नई रेललाइन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आजमगढ में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसके बाद गाजीपुर सिटी से दिलदारनगर जंक्शन के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही गंगा के आर-पार सपनों की ट्रेन दौड़ने लगेगी। इसको लेकर पूरे जनपद में खुशी का माहौल है।

देररात तक गाजीपुर सिटी स्टेशन पर लोकार्पण को लेकर भव्य तैयारी की जाती रही। कोलकाता-दिल्ली मेन रूट से बलिया-छपरा-मऊ रूट को जोड़ने के लिए बिछाई गई नई रेललाइन पर ट्रेनों के संचालन शुरू होने से पूर्वांचल के जिलों की बड़े शहरों से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ के अलावा बिहार के दूसरा छोर सीधा जुड़ाव हो जाएगा। 14 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ताड़ीघाट-मऊ नई रेलखंड के विस्तारीकरण परियोजना की आधारशिला रखी थी।

यह रेल लाइन दिल्ली-हावड़ा और वाराणसी-बलिया-छपरा रेलमार्ग को आपस में जोड़ेगी। यहां के लोग मुगलसराय से बाईपास करके हावड़ा से दिल्ली जा सकेंगे। एक नजर में परियोजना - 51 किमी लंबी ताड़ीघाट-मऊ नई रेललाइन परियोजना का दो चरणों में चल रहा कार्य।

1,766 करोड़ रुपये है परियोजना की कुल लागत

सोनवल से गाजीपुर सिटी स्टेशन तक रेल लाइन रेल कम रोड ब्रिज - 1027.5 मीटर रेल कम रोड ब्रिज की लंबाई - 16.9 मीटर चौड़ाई है इसकी चौड़ाई - 26000 टन है पुल का वजन - 52 स्पेरिकल बेयरिंग लगे हैं ब्रिज में - 4 ज्वाइंटर के अलावा 170 पैनल - 1.5 करोड़ की लागत से लगी है लाइट - 11 मार्च को हुआ था डीजल इंजन का ट्रायल। - 31 मार्च को इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था।

सौ की रफ्तार में दौड़ी ट्रेन

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा सोनवल से सिटी 9.600 व सोनवल से घाट की ओर जाने वाली 7.156 किमी लंबी दोनों नई रेल लाइन का लोकार्पण से पूर्व शनिवार को लाइट गुड्स ट्रेन के जरिए अंतिम और फाइनल ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। लाइट गुड्स ट्रेन दोनों नई रेल लाइनों एवं नवनिर्मित रेल पुल पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सिटी स्टेशन से चलकर सोनवल छह मिनट और सोनवल से घाट साढे.पांच मिनट में पहुंची।

रेलवे के अनुसार अब इन दोनों नये मार्गों पर करीब आधा दर्जन से अधिक बार ट्रायल होने एवं उसके सफल होने के बाद इन रूटों पर ट्रेनें अब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी।

24 बार किया गया ट्रायल, हर बार रहा सफल

सोनवल से सिटी जाने वाली नई लाइन का 13 मार्च 2023 को डीजल इंजन ट्रायल, 31 मार्च 2023 को इलेक्ट्रिक, 11 अक्टूबर 2023 लोडेड मालगाड़ी का ट्रायल के बाद 17 जून 2023 को इसका रेल संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण किया था। इसी तरह सोनवल से घाट जाने वाली नई रेल लाइन का 23 फरवरी को डीजल लोको, 27 फरवरी लोडेड मालगाड़ी एवं तीन मार्च को इलेक्ट्रिक लोको ट्रायल के सफल होने के बाद छह मार्च को रेल संरक्षा आयुक्त ने इस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान 24 बार ट्रायल किया गया। हर बार सफल रहा।

देहरादून : टैक्सी संचालकों ने मनमाने ढंग से बढ़ाया किराया

टैक्सी यूनियन के किराया बढ़ाने पर स्थानीय लोगों और होटल व्यवसायियों ने विरोध किया है। उन्होंने इसकी शिकायत परिवहन विभाग के अधिकारियों से करने की बात कही है।

देहरादून। चकराता और आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। इसके लिए कुछ लोगों ने मिलकर टैक्सी यूनियन का गठन किया। टैक्सी मालिकों ने अपने हिसाब से किराया भी तय कर लिया। टूरिस्ट डेवलपमेंट और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिंगबर सिंह चौहान, प्रशांत, वरुण सिंह, अमित, शुभम, रोहन आदि का कहना है कि टैक्सी यूनियन ने जो दरें तय की हैं, वह बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि चकराता से टाईगर फॉल के लिए 1800 रुपये, कनासर के लिए 2200 रुपये, लाखामंडल 3000 हजार और चकराता से महज 12 किमी दूर स्थित रामताल गार्डन के लिए 1000 किराया निर्धारित किया है। लोखंडी के लिए 1800 रुपये का किराया तय किया गया है। उन्होंने कहा कि किराये की नई दरों से पर्यटकों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कई पर्यटक इसे लेकर कई बार होटल मालिकों से शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने मानकों के अनुरूप किराया निर्धारित करने की मांग की।

फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है। राज्य परिवहन प्राधिकरण किराया निर्धारित करता है। लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

रावत सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन

गुजरात में अपग्रेड होंगे नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट, 1532 करोड़ मंजूर

परिवहन विशेष न्यूज

मोरबी जिले में नेशनल हाईवे 151ए के 12.4 किलोमीटर लंबे ध्रोल से आमरण तक का मार्ग बनेगा 4 लेन, जामनगर-राजकोट से कनेक्टिविटी होगी बेहतर

नई दिल्ली। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग को और बेहतर बनाया जाएगा। राज्य में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए केन्द्रीय मार्ग, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने 1532 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस राशि से मोरबी से जामनगर और राजकोट के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा, भरुच, सूरत जिलों में नेशनल हाईवे पर सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। इन दोनों ही रूट पर अभी लगने वाले समय में कमी आएगी। ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा।

नितिन गड़करी की ओर से गुजरात के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 151 ए के 12.4 किलोमीटर लंबे ध्रोल से आमरण तक के मार्ग को चार मार्गीय बनाने के लिए 625 करोड़ की राशि मंजूर की गई।

गड़करी ने कहा कि अमृतसर से जामनगर कॉरिडोर में यह हिस्सा अभी कम पड़ रहा था। इस कमी को इस हिस्से का विकास करके पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर से तीन राज्यों में चार रिफाइनरी और प्रोजेक्ट इलाके में आर्थिक सामाजिक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह मार्ग बनने के बाद ध्रोल-आमरण, पिपलिया मार्ग सेक्शन मोरबी और जामनगर औद्योगिक शहर को आपस में जोड़ेगा व गुजरात के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों से जोड़ेगा।

नेशनल हाईवे 151 ए और स्टेट हाईवे 25 के जामनगर-राजकोट सेक्शन के साथ भी जुड़ाव होगा। इससे इन शहरों के बीच का आवागमन में लगने वाले समय में एक घंटे की कमी आएगी। इससे वाहन खर्च बचेगा। ट्रैफिक कम होगा। नवलखी पोर्ट और नवलखी में आने वाले निवेश व माल सामान के परिवहन में भी इजाफा होगा। क्षेत्र में धार्मिक और पर्यटन कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके यह जानकारी दी।

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा नेशनल हाईवे 48

गड़करी ने एक और पोस्ट कर बताया कि गुजरात के वडोदरा, भरुच और सूरत जिले में 907 करोड़ रुपए के खर्च से नेशनल हाईवे 48 पर सेवाएं बेहतर बनाई जाएंगी। इस सेक्शन में वडोदरा से सूरत तक 15 किलोमीटर के इलाके में एप्रोच सहित के अतिरिक्त ढांचागत कार्य किए जाएंगे। इसकी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 48 स्वर्णिम चर्तुभुज योजना का एक हिस्सा है।

सबसे व्यस्त हाईवे में से एक माना जाता है। दिल्ली से शुरू होकर ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचता है। निर्माणाधीन वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस वे इस रूट को क्रॉस करता है। जिससे ट्रैफिक की आवाजाही को सरल बनाने के लिए नेशनल हाईवे 48 को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे 48 वडोदरा-सूरत विभाग के सभी हाल के पुलों को एलएचएस एवं आरएचएस दोनों ही तरफ से नए तीन और चार मार्गीय पुल के साथ बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। संभावित हादसे के स्थलों (ब्लैक स्पॉट) को चिन्हित कर उसे सुधारने के लिए ग्रेड सेपरेटर स्ट्रक्टर तैयार किए जाएंगे। इससे इस रूट पर चलने वाले वाहनों और माल ढुलाई के समय में कमी आएगी।

देश में पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी, रेलमंत्री ने दी खुशखबरी

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय रेल देश में पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ाने की तैयारियों में है। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संयंत्र में स्लीपर श्रेणी के कोच का अनावरण किया।

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) संयंत्र में वंदे भारत स्लीपर श्रेणी के कोच का अनावरण किया। बीईएमएल रक्षा मंत्रालय के तहत आता है और रक्षा, अंतरिक्ष, खनन, निर्माण, रेल और मेट्रो जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पाद बनाता है। इसे वंदे भारत के 160 स्लीपर डब्बे (10 ट्रेनसेट) बनाने का ठेका मिला है। वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के तीन संस्करण हैं- चेयर कार, स्लीपर और मेट्रो। जहां चेयर कार खंड पहले ही पेश किया जा चुका है और काफी लोकप्रिय है। वहीं वंदे भारत स्लीपर की पहली संरचना तैयार है। उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया, ₹अब इसकी साज-सज्जा का काम होगा। संरचना बनाना सबसे मुश्किल काम है। आज हम चर्चा करेंगे कि इसे और कैसे बढ़ाया जाए।₹ रेल मंत्री ने कहा, ₹हम पहले ट्रेनसेट का पांच से छह महीने तक परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही इसे लॉन्च किया जाएगा। स्लीपर ट्रेन उसी तकनीक पर आधारित है, जिस पर चेयर कार काम कर रही है।₹

रेलमंत्री ने कहा कि स्लीपर ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, ₹यात्रियों के ट्रेन में आसानी से प्रवेश करने के लिए सीढ़ी के फुट एरिया में सुधार किया गया है। शौचालयों में नया डिजाइन किया गया है और बेहतर एयर कंडीशनिंग है। नई तकनीक के साथ बेहतर सीट हैं। ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखा जाएगा और 99.99 फीसदी वायरस समाप्त हो जएंगे।

उन्होंने कहा कि नए युग की इस ट्रेन में वर्तमान में चल रही मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में बेहतर सुरक्षा सुविधाएं हैं। वैष्णव ने कहा, अन्य विकसित देशों में इसी तरह की सुविधाओं वाले एक कोच की विनिर्माण लागत करीब दस करोड़ रुपये आती है। हालांकि, एक वंदे भारत स्लीपर कोच की लागत करीब 8-9 करोड़ रुपये आती है।

बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय ने कहा, हमें इस मील के पत्थर का हिस्सा बनने की खुशी है, जो यात्रा के समय को कम करते हुए आराम और विश्व स्तरीय सुविधाओं की सुविधा प्रदान करेगा। हमारा उत्पादन पूरी क्षमता से काम कर रहा है और पूरी विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) और असेंबली प्रक्रिया बीईएमएल में की जाती है।

पार्टनर के साथ ये 4 चीजें करना, धीरे-धीरे घोंट सकती है रिश्ते का गला; आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलती

गौरव खरे

कपल्स को अपने रिश्ते को लंबा चलाने के लिए छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जरा सी भी गलती रिश्तों की सूरत बदल देती है। ऐसे में यदि आप अपने खूबसूरत रिश्ते को बदरंग होता नहीं देखना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर कर लें।

कई बार जाने-अनजाने हम अपने पार्टनर और रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पाते और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो साइलंट किलर की तरह आपके रिश्ते को बर्बाद करने लगता है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ताकि आपका लॉन्ग टर्म का रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे।

दबी हुई कड़वाहट का बाहर आना

अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आता है, तो उसी वक्त उसे पार्टनर के सामने एक्सप्रेस कर दें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप उस वक्त अपने गुस्से, निराशा और कुंठा को दबा लेते हैं, तो यह दबी हुई कड़वाहट भविष्य में जब बाहर निकलती है, तब रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कई सालों की शादी में ज्यादा होता है।

एक-दूसरे के बारे में पूर्वधारणाएं रखना

अगर कोई कपल इस बात को लेकर खुशी महसूस करता है कि वह दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो यह अच्छा संकेत भी हो सकता है और बुरा भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो लोग क्या इतने करीब हो सकते हैं कि वे एक-दूसरे का दिमाग पढ़ने लगें या फिर ये सिर्फ पूर्व धारणाएं हैं? ऐसे में सिर्फ यह मान लेना कि आप पार्टनर की पसंद-नापसंद को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके हिसाब से काम करना भी रिश्ते के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इसलिए पहले से चीजें मान लेने की बजाए पार्टनर को खुद अपनी भावनाएं जाहिर करने दें।

सरप्राइज न हो तो बोरिंग जिंदगी

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्ते का शुरुआती दौर इतना रोमांटिक और एक्साइटिंग क्यों होता है? यह वो समय होता है, जब दोनों पार्टनर एक-दूसरे के बारे में नई-नई चीजें जान रहे होते हैं। सरप्राइज किसी भी रिश्ते को एक्साइटिंग बना देता है।
लेकिन अगर समय के साथ रिश्ते में सरप्राइज कम होने लगे तो रिश्ता बोरिंग हो सकता है। लिहाजा कभी-कभार अचानक ही प्यार भरी बातें, डिनर डेट जैसी चीजें करते रहना चाहिए।

पार्टनर या रिश्ते को हल्के में लेना

कई बार मजबूत और स्थिर रिश्ते में भी दरार सिर्फ इस एक वजह से आ जाती है, क्योंकि एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर को या फिर अपने रिश्ते को हल्के में लेने लगता है।
यह इंसान की फितरत होती है कि जब इंसान किसी के साथ लंबे वक्त तक रहता है, तो उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। ऐसे में इस गलत आदत को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी रूटीन को बदलें।

बस 6 स्टेप्स में घर के गार्डन में उगाएं ब्रोकली, बाजार में नहीं करना पड़ेगा मोल भाव

यदि आपको ब्रोकली खाना पसंद है तो आप इसे बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में उगाकर खा सकते हैं। यहां हम आपको घर में ब्रोकली उगाने का स्टेप टू स्टेप तरीका बता रहे हैं।

गोभी की तरह दिखने वाला ब्रोकली सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें बहुत ही ताकतवर पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बाउल मूवमेंट को स्वस्थ रखने के साथ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा वेट लॉस में भी इसे कारगर बताया गया है।

वैसे तो आप इसे बाजार में बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपको मोल भाव से बचना है तो इसे अपने गार्डन में उगाना एक जबरदस्त आइडिया है। ऐसा करके आप बहुत ही सस्ते में ऑर्गेनिक ब्रोकली का लाभ उठा सकते हैं।

स्टेप 1

ब्रोकली उगाने के लिए चूने के साथ मिट्टी मिलाएं और इसे एक सप्ताह तक सुखाएं। प्रत्येक ग्रो बैग के लिए, 5 ग्राम चुना डालें। एक सप्ताह तक सीधी धूप में सुखाने के बाद, गोबर पाउडर या खाद जैसी जैविक खाद डालें।

आप इसमें कोको पीट भी मिला सकते हैं। सुनिश्चित करें कि गमले की मिट्टी ना तो ज्यादा सूखी हो ना ही ज्यादा गीली हो। क्योंकि इससे बीज खराब हो जाते हैं।

स्टेप 2

आप ब्रोकली के बीज या कटिंग दोनों की मदद से उगा सकते हैं। इसका बीज आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। इससे ब्रोकली को उगाने के लिए इसे ट्रे या गमले में बोएं और अंकुरित होने के लिए छोड़ दें।

स्टेप 3

ब्रोकली के कटिंग या अंकुरण को मिट्टी के मिश्रण के साथ ग्रो बैग के 1/4 हिस्से में लगाएं। जैसे-जैसे पौधा बढ़े, ग्रो बैग में मिट्टी डालते जाएं ताकि इसे तेजी से बढ़ने और बड़ी ब्रोकली के सिर बनाने में मदद मिल सके।

स्टेप 4

गमले की मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए यदि जरूरत पड़े तो इसमें समय-समय पर पानी भी डालते रहें। ध्यान रखें आपको मिट्टी में ज्यादा पानी नहीं डालना है। सिर्फ नमी को बरकरार रखने के लिए पानी का छिड़काव करना है।

स्टेप 5

जब ब्रोकली के बीज अंकुरित हो जाए तब इसे आप चाहे तो ट्रे या पॉट से निकालकर सीधे जमीन में भी लगा सकते हैं।

स्टेप 6

अंकुरित बीजों को एक जगह से दूसरे जगह पर लगाने से पहले इसे 30 मिनट के लिए स्यूडोमोनास तरल में पौधों की जड़ों को डुबोएं। ऐसा करने से इसकी जड़ें मजबूत होती है।

वक्त पर पकड़ना है काला मोतिया तो एक बार करें ये काम, पॉल्यूशन का जंजाल होगा खत्म

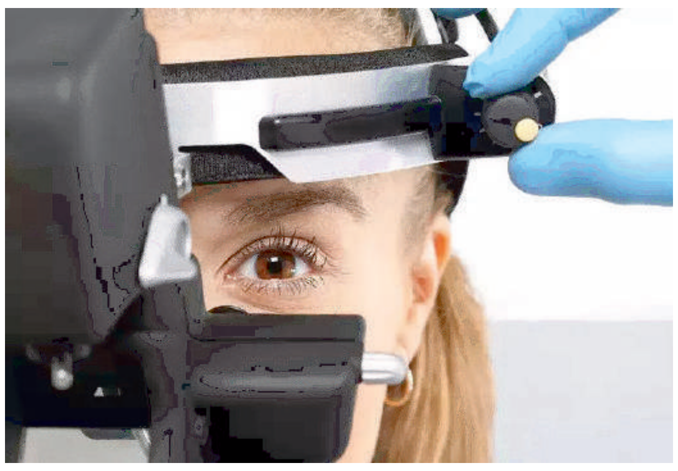

पॉल्यूशन के कारण लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी और गले में खराश जैसी परेशानियां हो रही हैं। इससे बचने के लिए विशेष टिप्स दिए गए हैं। आंखों की जांच और डाइलेट करने से आंखों की परेशानियों को समझना आसान होता है। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल मायोपिया को बढ़ावा देता है।

पॉल्यूशन ने अपना जोर लगाया हुआ है। लोगों को इस वजह से आंखों में जलन, सांसों की परेशानी, एलर्जी की शिकायत, गले में खराश समेत तमाम तरह की परेशानियों ने घेर रखा है। साथ ही मौसम बदल रहा है और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है।

ऐसे में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहतमंद बने रहने के लिए बेस्ट टिप्स। इन्हें अपनाकर आप खुद को अच्छी सेहत का तोहफा दे सकते हैं।

1. साल में एक बार आई चेकअप

साल में एक बार आंखों की जांच होनी चाहिए, वह भी आंखों को डाइलेट करके। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से टेस्टिंग होती है। लेकिन आंखों की अंदरूनी परेशानी का पता लगाने के लिए डाइलेट करने के खास लिक्विड (Tropicamide, Phenylephrine Hydrochloride) की चंद बूंदें आंखों में डाली जाती हैं।

इससे डॉक्टर को आंखों के भीतरी हिस्से, नसें आदि अच्छी तरह दिख जाती हैं। इससे आंखों की परेशानियों को समझना आसान हो जाता है। इस जांच का चलन ज्यादातर शुगर पेशेंट्स और उम्र से जुड़ी परेशानियों में होता है।

फिर भी इस तरह की जांच सभी के लिए होनी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। इससे काला मोतिया वक्त पर पकड़ में आ जाता है।

2. मोबाइल से दूरी

मोबाइल की जरूरत सभी को है। काफी संख्या में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी यह जरूरत लत बन गई है। लेकिन 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। इससे मायोपिया हो रहा है।

इसमें दूर की निगाह कमजोर हो जाती है। किसी शख्स को 6 फुट की दूरी पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई न दे तो इसका मतलब है कि वह मायोपिया का शिकार हो सकता है।

ज्यादातर बच्चे मायोपिया वाले ही होते हैं। आम रुटीन में हम एक मिनट में 20 से 25 बार पलकों को झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह महज 5 से 7 बार रह जाती है।

3. 20:20:20 फॉर्मूला

अगर कोई शख्स किसी से बात कर रहा हो, कहीं जा रहा हो तो वह स्वाभाविक तौर पर कभी नजदीक तो कभी दूर देखता रहता है। लगातार नजदीक देखने का मसला नहीं बनता। लेकिन जब कोई शख्स लगातार मोबाइल या लैपटॉप आदि की स्क्रीन को देखता रहता है तो 'दूरदर्शन' की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शख्स को 20:20:20 फॉर्मूले पर अमल करना जरूरी है यानी हर 20 मिनट बाद 20 बार पलकें झपकना, फिर लगातार 20 सेकंड तक 20 फुट या इससे दूर देखना चाहिए।

इससे आंखों को आराम मिलता है। साथ ही ड्राई आंखों की परेशानी भी कम होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करते हुए बार-बार पलकें झपकाएं। याद रखें, हर 5 सेकंड में एक बार पलकें झपकनी चाहिए।

चलो भारत... अब चीन को लेकर ना-ना! दुनियाभर में बदलाव के पीछे ये 5 बड़े कारण

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था अब चीन का विकल्प बनने का भरोसा बढ़ा रही है. इसकी वजह भारत के मजबूत प्रदर्शन के साथ ही चीन की कमजोर परफॉरमेंस भी है. एक तरफ भारत में जहां शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, एफडीआई में तेजी आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जबरदस्त निवेश हो रहा है. वहीं चीन में रियल एस्टेट संकट, पूंजी के आउटफ्लो और आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि भारत चीन का ₹वास्तविक₹ विकल्प बनने का मजबूत दावा पेश कर रहा है.

1. भारतीय शेयर बाजार ने दिखाया दमखम!

चीन के शेयर बाजार 2021 में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब गिरावट का सामना कर रहे हैं जिससे शंघाई, शेन्ज़ेन और हांगकांग के बाजारों से 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट कैप घट गई है. वहीं पिछले साल आई गिरावट के बाद एफडीआई जनवरी में 2023 के इसी महीने के मुकाबले 12 फीसदी घट गई. जबकि तेज आर्थिक रफ्तार के सहारे भारत का शेयर बाज़ार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है. भारत के शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू पिछले साल के आखिर में 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है. जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का मार्केट कैप दोगुना से ज्यादा होकर 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा. इतनी बड़ी मार्केट कैप का मतलब है कि दिग्गज वैश्विक निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे.

2. एमएससीआई इंडेक्स में भारत का दबदबा बढ़ा!

दरअसल, ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत ही चीन का विकल्प बन सकता है. कई मोर्चों पर जापान और जर्मनी भी चीन की जगह लेने का दम भर रहे थे. लेकिन इन दोनों ही देशों में छाए आर्थिक संकट और मंदी के हालातों ने इन्हें इस रेस से बाहर करके भारत को ये मौका दे दिया है. भारत को एक बड़ी ताकत एमएससीआई के इंडेक्स में वेटेज बढ़ने से भी मिलेगी. एमएससीआई ने फरवरी में कहा था कि वो अपने उभरते बाजारों के इंडेक्स में भारत के वेटेज को 17.98 परसेंट से बढ़ाकर 18.06 फीसदी करेगा जबकि चीन के वेटेज को घटाकर 24.77 फीसदी करेगा. कुछ बरस पहले तक इस इंडेक्स में भारत का वेटेज महज 7 फीसदी था. एमएससीआई के इंडेक्स में अलग अलग देशों की ये वेटेज दुनियाभर के संस्थागत निवेशकों को रकम के आवंटन में मदद करती है.

3. चीन से ज्यादा रहेगी भारत की ग्रोथ!

कुछ यही हाल भारत की विकास दर को लेकर लगाए गए आईएमएफ के अनुमानों में भी झलकता है जिसने भारत की विकास दर साढ़े 6 फीसदी और चीन का ग्रोथ रेट 4.6 परसेंट रहने का अनुमान लगाया है. इसके अलावा भारत के पक्ष में बढ़ती युवा आबादी से लेकर बढ़ती फैक्टरियों तक काफी कुछ है जो इसे वाकई चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकता है. लेकिन इसकी आगे की चाल काफी हद तक 2024 के आम चुनाव के बाद बनने वाली स्थिर सरकार तय करेगी. माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करते हैं तो फिर अगले 5 साल के लिए आर्थिक नीतियों को लेकर दुविधा नहीं रहेगी और निवेशक लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं.

2027 तक बनेगा भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी!

जेफ़रीज़ के विश्लेषकों को उम्मीद है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठीक उसी तरह से निवेश किया जा रहा है जैसा तीन दशक पहले चीन में शुरु किया गया था. यहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की शुरुआत हो रही है जिसमें रोड नेटवर्क, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे के निर्माण पर भारी भरकम रकम खर्च की जा रही है.

4. चीन जैसे दूसरे बाजार की कंपनियों को तलाश!

भारत को एक बड़ा फायदा दुनियाभर की कंपनियों की चीन+1 की नीति से भी मिल रहा है. दरअसल, चीन पर कंपनियों की जरुरत से ज्यादा निर्भरता ने कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन को संकट में डाल दिया था. वहीं चीन के अमेरिका समेत कई देशों के साथ जारी भू-राजनीतिक तनाव ने भी आग में घी का काम किया है. ऐसे में कंपनियां अब सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश के भरोसे नहीं रहना चाहती हैं. वो इसका विस्तार कर रही हैं जिसमें अपनी सस्ती लेबर और लागत की वजह से भारत एक प्रमुख विकल्प के तौर पर उभर रहा है. एपल ने तो भारत में अपने कुल आईफोन उत्पादन का 7% बनाना शुरु कर दिया है. कंपनी की वेंडर फॉक्सकॉन और कुछ दूसरी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी कह चुके हैं कि उनकी कंपनी अतिशीघ्र भारत में निवेश करना चाहती है.

5. घरेलू निवेशक बने भारत की सबसे बड़ी ताकत

भारत की क्षमता को लेकर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि चीन से आने वाली सारी रकम को भारत में इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है. इसकी एक वजह ये है कि भारत के मुकाबले चीन की इकॉनमी करीब 5 गुना बड़ी है. लेकिन इसके बावजूद भारत की ताकत को कम करके इसलिए भी नही आंका जा सकता है क्योंकि भारत में तेजी आने की बड़ी वजह घरेलू कारण हैं और विदेशी धन पर इसकी निर्भरता कम है. भारत के रिटेल निवेशकों की इक्विटी बाजार में 9 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि विदेशी निवेशकों के पास 20 परसेंट से कुछ कम हिस्सेदारी है. हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद 2024 की दूसरी छमाही में भारत में विदेशी निवेश बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में भारत घरेलू

भारत और चीन के बीच फिर गरज सकते हैं टैंक, आर.यू. एस.आई. रिपोर्ट में दावा किया गया

भारत और चीन के बीच अगले कुछ सालों के भीतर जंग छिड़ सकती है। भू-राजनीतिक मामलों के जानकारों ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में 2025 से 2030 के बीच भारत और चीन के बीच दोबारा जंग हो सकती है। जंग की प्रमुख वजह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सी.पी.ई.सी) को बताया गया है। जानकारों का कहना है कि चीन अपने काशगर एनर्जी प्लांट को लेकर डरा हुआ है। इसका रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर जाता है। ऐसे में बीजिंग को डर है कि यदि किसी पड़ोसी देश ने उस पर हमला कर दिया तो उसकी एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। ब्रिटिश थिंक टैंक द रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीटयूट (आर.यू. एस.आई.) ने अपनी रिपोर्ट के शीर्षक 'भारतीय क्षितिज पर युद्ध के बादल' में यह टिप्पणी की गई है. रिपोर्ट के लेखक समीर टाटा ने कहा कि लद्दाख के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2025 से लेकर 2030 तक जंग छिड़ सकती है. उन्होंने कहा कि चीन भारत के पूर्वी हिस्से को उर्जा सुरक्षा के खतरे के रूप में देखता है. चीन की यह हरकत दोनों देशों को जंग की ओर धकेल सकती हैं.

चीन के एनर्जी प्रोजेक्ट पर खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन को लगता है कि शिनजियांग प्रांत में स्थित एनर्जी के बड़े काशगर प्रोजेक्ट हमले या कब्जे का शिकार हो सकता है। चीन का डर इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजिंग के पश्चिमी प्रांत का रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर जाता है।

शत्रुतापूर्ण स्थिति में भारत इस मार्ग का उपयोग कर सकता है। काशगर एनर्जी प्रोजेक्ट ईरान के साथ तेल और भूमि गैस पाइपलाइन से जुड़ा है जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से होकर जाता है। यह चीन की उर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण केंद्र है। जंग की प्रमुख वजह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सी.पी.ई.सी.)को बताया गया है। जानकारों का कहना है कि चीन अपने काशगर एनर्जी प्लांट को लेकर डरा हुआ है, इसका रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर जाता है। ऐसे में बीजिंग को डर है कि यदि किसी पड़ोसी देश ने उस पर हमला कर दिया तो उसकी एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। ब्रिटिश थिंक टैंक द रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीटयूट (आर.यू.एस.आई.) ने अपनी रिपोर्ट के शीर्षक 'भारतीय क्षितिज पर युद्ध के बादल' में यह टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट के लेखक समीर टाटा ने कहा कि लद्दाख के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2025 से लेकर 2030 तक जंग छिड़ सकती है। उन्होंने कहा कि चीन भारत के पूर्वी हिस्से को उर्जा सुरक्षा के खतरे के रूप में देखता है। चीन की यह हरकत दोनों देशों को जंग की ओर धकेल सकती हैं।

चीन के एनर्जी प्रोजेक्ट पर खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन को लगता है कि शिनजियांग प्रांत में स्थित एनर्जी के बड़े काशगर प्रोजेक्ट हमले या कब्जे का शिकार हो सकता है। चीन का डर इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजिंग के पश्चिमी प्रांत का रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर जाता है। शत्रुतापूर्ण स्थिति में भारत इस मार्ग का उपयोग कर सकता है। काशगर एनर्जी प्रोजेक्ट ईरान के साथ तेल और भूमि गैस पाइपलाइन से जुड़ा है जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से होकर जाता है। यह चीन की उर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण केंद्र है।

चीन की बढ़ चुकी है चुनौती

भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल एम नरवने ने कहा कि भारत गलवान घाटी की हिंसा के बाद बेहद सतर्क हुआ है और सीमा पर तैनाती बढ़ाई है। यूरेशियन टाइम्स से वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख और काराकोरम पास चीन की दीर्घकालिक रणनीति का लंबे समय से हिस्सा रहा है। चीन यह जानता है कि यह उसके सी.पी.ई.सी. प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। नरवने ने कहा कि यदि बीजिंग को लगता है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या सी.पी.ई.सी. प्रोजेक्ट, पीओके, तिब्बत में उसकी पहुंच को सीमित कर सकते हैं तो यह 1962 के बाद बड़ा बदलाव है। 1962 की जंग में भारत ने अपने सैनिक और जमीन दोनों ही गंवा दी थी। भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल एम नरवने ने कहा कि भारत गलवान घाटी की हिंसा के बाद बेहद सतर्क हुआ है और सीमा पर तैनाती बढ़ाई है। यूरेशियन टाइम्स से वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख और काराकोरम पास चीन की दीर्घकालिक रणनीति का लंबे समय से हिस्सा रहा है। चीन यह जानता है कि यह उसके सी.पी.ई.सी. प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। नरवने ने कहा कि यदि बीजिंग को लगता है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं या सी.पी.ई.सी. प्रोजेक्ट, पीओके, तिब्बत में उसकी पहुंच को सीमित कर सकते हैं तो यह 1962 के बाद बड़ा बदलाव है। 1962 की जंग में भारत ने अपने सैनिक और जमीन दोनों ही गंवा दी थी।

दक्षिणी दिल्ली सीट पर रहा है गुर्जर मतदाताओं का वर्चस्व, आप-भाजपा ने इन पर लगाया दांव; जानिए समीकरण

परिवहन विशेष न्यूज

दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा और AAP के बीच चुनाव में कड़ी टक्कर देखने मिल सकती है। इस सीट पर हमेशा गुर्जर मतदाता का वर्चस्व रहा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने सीट पर गुर्जर प्रत्याशी बनाए हैं। भाजपा ने रामवीर सिंह बिधूड़ी और आप ने सहीराम पहलवान को अपना चेहरा बनाया। इस सीट पर गुर्जर बनाम गुर्जर की भी स्थिति बन सकती है।

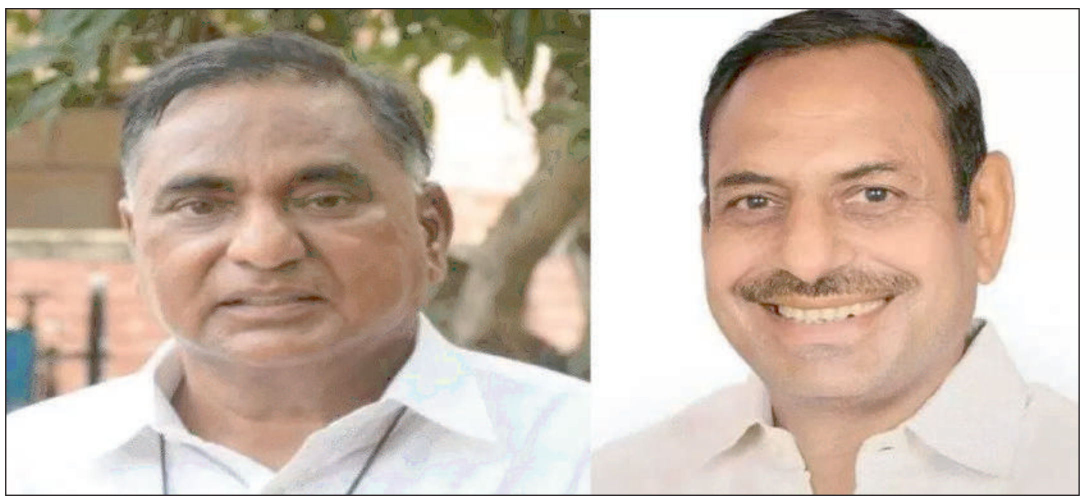

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच चुनाव में कड़ी टक्कर देखने मिल सकती है। इस सीट पर हमेशा गुर्जर मतदाता का वर्चस्व रहा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने सीट पर गुर्जर प्रत्याशी बनाए हैं। भाजपा ने रामवीर सिंह बिधूड़ी और आप ने सहीराम पहलवान को अपना चेहरा बनाया। इस सीट पर गुर्जर बनाम गुर्जर की भी स्थिति बन सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा प्रत्याशी जातीय समीकरण को साधने में कामयाब रहता है।

राजधानी की सबसे हाट मानी जाने वाली दक्षिणी दिल्ली सीट पर कुल 22 लाख 21 हजार 445 मतदाता है। इस लोकसभा में कुल 54 गांव हैं। इनमें से 22 गावों में गुर्जर बहुल है। इन गांवों में करीब साढ़े चार लाख गुर्जर है। इनमें मुख्य रूप से तुगलकाबाद, बदरपुर, छतरपुर, भाटी कलां, आली, मदनपुर, सतबड़ी और चंदनहोला शामिल हैं। इसके अलावा शहरी हिस्से में गुर्जर की संख्या काफी है। इस वजह से सीट पर प्रत्याशी को जिताने में गुर्जर जाति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।

2019 की हार के बाद आप ने भी गुर्जर प्रत्याशी बनाया

इस बार गुर्जर मतदाता को साधने के लिए आप ने भी गुर्जर उम्मीदवार सहीराम पहलवान को मैदान में उतारा है, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में आप ने पंजाबी समुदाय के राघव चड्डा को प्रत्याशी बनाया था। राघव को भाजपा के गुर्जर प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने हरा दिया था। जबकि भाजपा वर्ष 2014 से इस सीट पर गुर्जर को ही उम्मीदवार घोषित कर रही है।

रालोद-भाजपा गठबंधन के जाट भी मुख्य भूमिका में

इस सीट पर गुर्जर के बाद करीब 17 गांव जाट बहुल हैं। इनमें मुख्य रूप से देवली, वसंत कुंज, नेब सराय, बिजवासन और संगम विहार के कुछ हिस्से हैं। यहां पर जाटों की आबादी करीब ढाई लाख है। जाटों की पसंदीदा पार्टी रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के जाट मतदाता भाजपा के पास जाने की प्रबल संभावना है। वहीं, कालकाजी, गोविंदपुरी, साकेत, महरौली समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में पंजाबी वोटर हैं।

लोकसभा क्षेत्र की 10 में नौ विधानसभा सीटों पर आप का कब्जा

दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के दायरे में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकरनगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर शामिल हैं। इनमें से नौ सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, एक सीट पर बीजेपी काबिज है।

विधानसभा में आप और लोकसभा में भाजपा को चुन रहे मतदाता

पिछले विधानसभा चुनाव में आप को यहां 54 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे। पिछले दो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि यहां के अधिकतर मतदाता सांसद के चुनाव में भाजपा को वोट कर रहे हैं। जबकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं।

85 फीसदी हिंदू और दूसरे नंबर पर 9.1 फीसदी मुस्लिम मतदाता

दक्षिणी दिल्ली सीट की पर पहले नंबर पर 85 फीसदी से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग 9.1 फीसदी के साथ मुस्लिम मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर 2.4 फीसदी आबादी के साथ सिख हैं। इसके अलावा यहां जैन 0.4 और बौद्ध 0.14 फीसदी हैं। यहां पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 15.39 फीसदी है।

पूर्वांचल के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में

दक्षिणी दिल्ली सीट पर पूर्वांचली मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। कई विधानसभा सीटों पर यह बड़ी संख्या में हैं। यह देवली विधानसभा में 31, अंबेडकर नगर में 26, संगम विहार में 26 और तुगलकाबाद में करीब 24 प्रतिशत मतदाता हैं।

भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री ने की शिरकत, फिर एक बार मोदी सरकार का आह्वान

राष्ट्र के विकास के साथ विरासत को भी संजोने का काम पीएम मोदी ने किया – मीनाक्षी लेखी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्र के विकास के साथ-साथ विरासत को भी संजोने का काम किया है। वहीं देश की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण का काम भी इन वर्षों में हुआ है। यह बात केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाजपा द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए कही ।

उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में जो बदलाव दिखने चाहिए थे वह बदलाव केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद देखने को मिले है। 2014 से पहले देश में तरक्की का अकाल था, हर तरफ घोटाले ही घोटाले थे। उस समय देश की जनता के जो सपने पूरे नही हो सके उन्हीं सपनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत के रूप में बुनते है, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं । उन्होंने कहा कि भारत अब तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। आने वाले वर्षों में देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मोदी की गारंटी है। वर्ष 2014 के बाद लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। लोगों ने बदलते भारत की तस्वीर देखी है । मातृ शक्ति को 75 वर्षों में जो अधिकार मिलने चाहिए थे वे उन्हें मोदी सरकार ने दिलाए हैं। वहीं घर घर गैस कनेक्शन, हर घर में नल से जल, आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का काम भी मोदी सरकार ने किया। देश में महिलाओं के एक लाख से ज्यादा स्वयं सेवी समूह हो गए है जिनसे लगभग 8- 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं वहीं एक लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के माध्यम से भी युवा प्रगति कर रहे हैं । इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार का 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है । देश में पहले 70 से कम एयरपोर्ट थे जिनकी संख्या आज 150 से ज्यादा हो गई है। सड़क मार्गों की बात हो या रेलवे की हर क्षेत्र में विकास हो रहा है जिसका सीधा फायदा देश के उद्योग जगत को भी मिल रहा है। वही धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का बदला हुआ चेहरा सभी के सामने आया है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या श्री राम मंदिर की स्थापना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संकल्प शक्ति से हर कार्य को सुशासन के साथ सिद्ध किया है।

उन्होंने कहा कि देश में लगभग 11 करोड बैंक खाते थे जब की केंद्र की मोदी सरकार ने मात्र 4 महीनों में 52 करोड खाते खोल कर दिए। जनधन खाता, आधार नंबर और मोबाइल को जोड़कर फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को कम करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। 75 साल के इतिहास में खेलों में इस बार सबसे ज्यादा मेडल भारत की झोली में आए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बहुत आगे निकल गया है। देश में आज 46% डिजिटल पेमेंट हो रही है। इंटरनेशनल ट्रेड हो या एक्सपोर्ट हर क्षेत्र में भारत का नाम विश्व पटल पर छाया हुआ है। कोरोनाकाल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर बाहरी वैक्सीन खरीदने का दबाव था लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी खुद की वैक्सीन लेकर आया और चिकित्सा के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी।

जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अंत में उपस्थित प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों को खड़े होकर संकल्प भी दिलाया और सभी से नमो ऐप डाउनलोड करने का भी आह्वान किया । इससे पूर्व प्रारंभ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने विदेश राज्य मंत्री के प्रथम बार भीलवाड़ा आगमन पर जिला संगठन एवं समस्त जिलेवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, सांसद सुभाष बहेडिया, लोकसभा सहप्रभारी गजपाल सिंह, जिला प्रमुख बरजीदेवी भील, विधायक उदयलाल भडाणा, गोपीचंद मीणा, गोपाल खंडेलवाल, जब्बरसिंह सांखला, लादूलाल पितलिया, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, बालूराम चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख शक्तिसिंह हाड़ा भी मंचासीन थे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का सफल संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी ने किया।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री भगवतीप्रसाद जोशी, राजकुमार आंचलिया, वेदप्रकाश खटीक, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल आचार्य, छैलबिहारी जोशी, मंजू चेचाणी, शंकरलाल जाट, अविनाश जीनगर, मुकेश धाकड़, लक्ष्मणसिंह राठौड़, रतनलाल अहीर, सुखलाल गुर्जर, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, गोपाल तेली, अमित सारस्वत, प्रतिभा माली, अमरसिंह चौहान, राधेश्याम कुमावत, जमनालाल सेन, रेखा अजमेरा, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष पंकज मानसिंहका, मीडिया संयोजक महावीर समदानी, अध्यक्षीय प्रवास प्रमुख मनोज बुलानी, आईटी संयोजक अजय नौलखा, सोशल मीडिया सहसंयोजक मीनाक्षी नाथ, आकाश मालावत, मोर्चा अध्यक्ष मंजू पालीवाल, राजेश सेन, कुलदीप शर्मा, पूरण डीडवानिया, महेंद्र मीणा, इमरान कायमखानी, विधानसभा संयोजक अनिल जैन, अशोक तलाईच, मंडल अध्यक्ष मनीष पालीवाल, पियूष डाड, घनश्याम सिंघीवाल, लवकुमार जोशी, मुकेश चेचाणी, रितुशेखर शर्मा, जितेंद्र शर्मा, पियूष सोनी, पंकज प्रजापत, भरतसिंह राठौड़, नागेंद्र सिंह, इंदु बंसल, नेहा नागर, अनुराधा कंवर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं शहर के प्रबुद्धजन जिनमे सीए, सीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, लेक्चरार, विभिन्न समाजों एवं एनजीओ के पदाधिकारी, खिलाड़ी, वरिष्ठ नागरिक, पेंशनर्स, पूर्व सैनिक, कलाकार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

विदेश राज्य मंत्री ने विशिष्ट प्रतिभाओं को किया सम्मानित - भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जिले की विशिष्ट प्रतिभाओं को श्रीफल भेंट कर, दुपट्टा व शॉल पहनाकर सम्मानित किया। जिनमे पद्मश्री नामित जानकीलाल भांड, सेवानिवृत्त सेशन जज शिवकुमार व्यास, पांडेजी, सेवानिवृत्त आईएएस एन के जैन, श्रीवास्तवजी, सेवानिवृत्त आरएएस शोभालाल मूंदड़ा, अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र कटारिया, शतरंज कोच कैलाश डाड, फड़ पेंटिंग एक्सपर्ट कल्याण जोशी, कलाकार केजी कदम, सेवानिवृत्त पीएमओ केसी पवार, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर माया माली, स्वर्ण पदक विजेता करण पूरी, पर्यावरणविद नारायणलाल भदाला, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पवन साहू, सेवानिवृत वन अधिकारी ललित सिंह राणावत, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता एस एस गंभीर, लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालिका टीना लोहार आदि का सम्मान किया गया ।

विदेश राज्य मंत्री ने एलईडी प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया - विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने टाउन हॉल परिसर में ही भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत एलईडी और डिजिटल प्रचार रथों को झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा इन एलईडी रथों के माध्यम से मोदी सरकार की गरीब कल्याणकारी उपलब्धियां का प्रचार करेगी। इसके साथ ही रथ में सुझाव पेटी भी रखी गई है, इन सुझाव पेटी के माध्यम से बीजेपी अपने संकल्प पत्र को लेकर लोगों से सुझाव लेगी। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में ये रथ सभी आठों विधानसभाओं में पहुंचेंगे और योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ जनता के सुझाव भी एकत्र करेंगे।

विदेश राज्य मंत्री ने किया भाजपा कार्यालय का अवलोकन - विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की उपस्थिति में भाजपा जिला कार्यालय का भी अवलोकन किया और मौजूद पदाधिकारियो की एक संक्षिप्त बैठक भी ली।

दिल्ली में 11वें मेडिकल कॉलेज की होगी शुरुआत, 1500 बेड के अर्धसैनिक बल अस्पताल को टेकओवर करेगा एम्स

मैदानगढ़ी में स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआइएमएस) को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संचालित करेगा। 1500 बेड के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का एम्स ने शनिवार को टेकओवर किया। सीएपीएफआईएमएस और एम्स के बीच शनिवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अब यह दिल्ली का 11वां मेडिकल कॉलेज होगा। इसमें शुरुआत में 100 सीटें पर स्नातक में दाखिले दिए जाएंगे।

नई दिल्ली। मैदानगढ़ी में स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआइएमएस) को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) संचालित करेगा। 1500 बेड के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का एम्स ने शनिवार को टेकओवर किया। सीएपीएफआईएमएस और एम्स के बीच शनिवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। अब यह दिल्ली का 11वां मेडिकल कॉलेज होगा। इसमें शुरुआत में 100 सीटें पर स्नातक में दाखिले दिए जाएंगे। अस्पताल में सीएपीएफ कर्मचारियों, उनके आश्रितों, पेंशन भोगियों, सीजीएचएस लाभार्थियों, एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों के साथ आम लोगों का उपचार भी किया जाएगा। एम्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने सभी सीएपीएफ कर्मचारियों, उनके आश्रितों, पेंशनभोगियों, सीजीएचएस लाभार्थियों व सामान्य लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएपीएफआईएमएस (CAPF IMS) की कल्पना की है।

कैबिनेट ने सीएपीएफआईएमएस को एम्स के परिसर के रूप में चलाने के लिए 15वें वित्त आयोग चक्र में 2207.50 करोड़ के बजटीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। दैनिक जागरण ने पिछले वर्ष सीएपीएफआईएमएस को एम्स द्वारा टेकओवर करने की प्रक्रिया पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अब इस पर मुहर लग गई है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2014 में मैदान गढ़ी में सीएपीएफआईएमएस के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसके तहत करीब 1500 बेड की क्षमता रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज, छात्रावास, डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण शुरू किया गया। अब सभी काम पूरा हो चुका है। फरवरी 2021 में गृह मंत्रालय ने इस संस्थान में शुरुआती चरण में 500 बेड के जनरल व 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन शुरू करने के लिए ईओआइ (एक्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) जारी किया था। लेकिन, ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा था। इसलिए एम्स इसे टेकओवर करने की योजना बनाई थी। एम्स के मुख्य अस्पताल और विभिन्न सेंटरों को मिलाकर करीब तीन हजार से अधिक बेड उपलब्ध हैं। नए अस्पताल के जुड़ने 1500 बेड और जुड़ जाएंगे और लोगों को लंबी वेटिंग से मुक्ति मिल सकेगी।

संगठन को मजबूत करने में जुटा अकाली दल, नेताओं को दी जा रही जिम्मेदारी

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) को ध्यान में रखकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) के नेता दिल्ली में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं को नियुक्ति पत्र दी गई। पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने दिल्ली के सिखों से अकाली दल को मजबूत करने का आह्वान किया।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) को ध्यान में रखकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद बादल) के नेता दिल्ली में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं को नियुक्ति पत्र दी गई। पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने दिल्ली के सिखों से अकाली दल को मजबूत करने का आह्वान किया। लोगों से पंजाब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों व मित्रों से भी अकाली दल को समर्थन देने की अपील करने को कहा। शिअद बादल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीएमसी) की सत्ता संभालने वालों ने सिख विचारधारा, सिद्धांतों व सिखों की मांगों से मुंह मोड़ लिया है। शिअद बादल की कोर कमेटी के सदस्य मनजीत सिंह जीके ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से किसी मुद्दे पर सिखों की असहमति हो सकती है, लेकिन वह अकाली दल के विरोध में नहीं हैं। जब भी पंथ को जरूरत पड़ी है, अकाली उनके साथ खड़े हुए हैं। परमजीत सिंह राणा व डॉ. हरमीत सिंह को कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सतनाम सिंह खालसा को ट्रांसपोर्ट इकाई का चेयरमैन व मोहिंदर सिंह को महासचिव बनाया गया है।

न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और मलेशिया में फैला नेटवर्क, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर मॉड्यूल का सरगना जाफर

नई दिल्ली। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर मॉड्यूल के सरगना जाफर सादिक को गिरफ्तार किया है। पिछले माह एनसीबी ने कुछ तस्करों को गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जाफर सादिक का नेटवर्क भारत के अलावा न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया और मलेशिया में फैला हुआ है। तस्करी से अर्जित पैसों को आरोपित विभिन्न धंधों जैसे फिल्म उद्योग, कंस्ट्रक्शन व होटल व्यापार आदि में निवेश करता था। इसे 50 किलो स्यूडोफेड्रिन के साथ दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसकी गिरफ्तारी एनसीबी व अन्य अंतर एजेंसियों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का परिणाम माना जा रहा है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह का कहना है कि एनसीबी ने न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलियाई अधिकारियों के सहयोग से इस बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है।

गुलाबी रंग में रंगे राजधानी के रास्ते! फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन-2024, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला स्वास्थ्य, फिटनेस और समावेशिता को बढ़ावा देना था

विशेष-सक्षम सदस्यों, पैरा-एथलीटों, ट्रांसजेंडर और बुजुर्गों ने भी एक साथ मिलकर “पिंक साइक्लोथॉन” का मनाया जश्न

सत्या पाण्डे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट के पथ पर चलते हुए, स्किल इंडिया, एन.सी.आई.ई.टी., एन.एस.डी.सी., एफ़.आई.सी.सी.आई., एस.पी.ई.एफ.एल.-एस.सी. और फिट इंडिया के सहयोग से एस.पी.ई.एफ.एल.-एस.सी. द्वारा आयोजित फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन-2024 के पहले संस्करण का सफलतापूर्वक आगाज़ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, शुक्रवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक प्रतिष्ठित जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला स्वास्थ्य, फिटनेस और समावेशिता को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम मिशन एफ.आई.टी. इंडिया की निदेशक सुश्री एकता विश्नोई और निदेशक श्री अरुण कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था।

इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा साइकिल दौड़ एवं जुम्बा जैसी गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न रोचक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया जिससे प्रतिभागियों और दर्शकों को समान रूप से शामिल किया जा सके।

इस अवसर पर सुश्री प्रीति मस्के (साइकिल चालक), सुश्री शहीदा परवीन गांगुली (उप पुलिस अधीक्षक जम्मू और कश्मीर पुलिस), सुश्री वीता दानी (संस्थापक, दानी फाउंडेशन), सुश्री अनीता सिंह तंवर (सामाजिक कार्यकर्ता) और सुश्री खुशवीन कौर (इनहैन्स्ड लैब इंडिया) उत्साही प्रतिभागियों को प्रेरित करने और दर्शकों को “आत्मरक्षा - महिलाओं का अधिकार” का संदेश देने के लिए वहां मौजूद थे।

सुश्री प्रीति मस्के ने कहा कि “साइकिल हमें फिट रखने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है।” उनका समर्थन करते हुए सुश्री शहीदा परवीन गांगुली ने कहा कि “महिलाओं को अधिक आत्म-जागरूक होना चाहिए और परिस्थितियों के अपने पक्ष में होने का इंतजार करने के बजाय, उन्हें वर्तमान में उपलब्ध साधनों से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए।” सुश्री वीता दानी और सुश्री अनिता सिंह तंवर ने यह भी कहा कि “आधुनिक दुनिया की महिलाओं के लिए अपने शरीर को फिट रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है।” “केवल फिट महिलाएं ही देश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान दे सकती हैं।” कहते हुए सुश्री खुशवीन कौर ने उनकी बात से सहमति जताई।

इस कार्यक्रम की खासियत यह रही कि विशेष-सक्षम सदस्यों, पैरा-एथलीटों, ट्रांसजेंडर और बुजुर्गों ने भी एक साथ मिलकर “पिंक साइक्लोथॉन” का जश्न मनाया। एक दूरदर्शी प्रतिनिधित्व के रूप में, खेल- शारीरिक शिक्षा-फिटनेस और अवकाश क्षेत्र कौशल परिषद के कार्यकारी सी.ई.ओ. श्री तहसीन जाहिद ने कहा, “यह कार्यक्रम समाज के लिए महिलाओं की शक्ति का एहसास करने और जनता में नियमित फिटनेस के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए महज एक बार का प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि हम जल्द ही देश के अन्य शहरों में भी इस कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहे हैं।” इस कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागियों को ढेर सारी प्रेरणा के साथ भागीदारी के प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हुए। कार्यक्रम के आयोजक प्रतिभागियों का उत्साह और दिल्ली-एनसीआर के दूर-दराज के इलाकों से दर्शकों के रूप में आए लोगों का उत्साह देखते हुए ‘फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन’ के अगले संस्करण को जल्द ही लाने के लिए प्रेरित हुए हैं। इस अवसर पर एस.पी.ई.एफ.एल. के अधिकारी राकेश कुमार, अमित खन्ना, ममता सिंह और अन्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भागीदार संगठनों के साथ कार्यक्रम की मेजबानी की।

हॉस्टल में खाना खाने के बाद बिगड़ी 200 से अधिक छात्रों की तबीयत, योगी सरकार ने मांगी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के आर्यन रेजीडेंसी और लॉयड के हॉस्टल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाना खाने से 200 से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। छात्रों की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पतालत में भर्ती कराना पड़ा है। सभी छात्रों का इलाज चल रहा है। कई छात्रों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है।

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के आर्यन रेजीडेंसी और लॉयड के हॉस्टल में रह रहे 200 से अधिक छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए।

इसके बाद पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। इस मामले का संज्ञान अब योगी सरकार ने भी ले लिया है। सरकार ने मामले की रिपोर्ट मांगी है।

तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद काफी छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।

वहीं कुछ का उपचार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है, फूड विभाग को जानकारी दे दी गई है।

200 से अधिक छात्रों की तबीयत बिगड़ी

पुलिस का कहना है कि छात्रों की संख्या 200 से अधिक है। दर्जनों छात्रों को उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। फूड विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है, उनकी टीम खाने की जांच के लिए पहुंच रही है।

तीन अस्पतालों में भर्ती हैं छात्र

बीमार छात्रों को कैलाश अस्पताल ग्रेटर नोएडा, वैक्सन अस्पताल नॉलेज पार्क व शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मेस इंचार्ज हिरासत में

इतनी बड़ी घटना के बाद जांच कर रही पुलिस ने मेस के इंचार्ज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

योगी सरकार ने लिया संज्ञान

योगी सरकार के गृह विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर पुलिस व जिला प्रशासन से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम वेद प्रकाश पांडे कैलाश अस्पताल पहुंचकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।

छात्रों ने बताया है कि शुक्रवार को उन लोगों ने महाशिवरात्रि पर व्रत रखा था। व्रत के लिए कुट्टू के आटे की पूरी, आलू और टमाटर की सब्जी व कुछ अन्य चीज बनाई गई थी, जिसे खाने के बाद वह बीमार हुए हैं। एपीजे कॉलेज के 12 छात्र अब तक उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल पहुंच चुके हैं।

बंद मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा; शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा

गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र के बिसोखर गांव में एक बंद पड़े मकान में शुक्रवार रात आग लगने की सूचना मिली। हादसे में लाखों की कीमत का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम व पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस दौरान मकान में कोई नहीं था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र के बिसोखर गांव में बंद पड़े मकान में शुक्रवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। हादसे में लाखों की कीमत का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम व पुलिस ने आग पर काबू पाया।

गनीमत रही कि इस दौरान मकान में कोई नहीं था। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिसोखर गांव में एक तीन मंजिला बिल्डिंग हैं, जिसके तीसरे फ्लोर पर मनवीर का मकान है। मनवीर परिवार समेत किसी काम से शनिवार को बाहर गए थे। इस बीच अचानक उनके मकान पर आग लग गई। मकान से धुंआ निकलता देख पड़ोसी अंकित ने डायल 112 पर सूचना दी। जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची।

दो फायर टैंकर ने पाया काबू

आसपास के लोगों की मदद से बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन आग का विकराल रूप देखते हुए दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम ने दो फायर टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया। मनवीर को भी सूचना दी गई।

शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

एफएसओ मोदीनगर अमित कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शार्ट सर्किट ही सामने आ रहा है। हादसे में कोई हताहत नहीं है। समय रहते टीम ने आग पर काबू पा लिया।

पांच हजार रुपये के लिए सात साल की बच्ची को किया अगवा, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने ही एक बच्ची को अगवा कर झांसी ले गया। आरोपी ने बच्ची के पिता से पांच हजार रुपये की फिरौती मांगी। इसकी जानकारी गाजियाबाद पुलिस को दी गई। पुलिस ने कॉल ट्रैक किया तो वह झांसी की निकली। फिर झांसी पुलिस की मदद से आरोपी पड़ोसी मदन को गिरफ्तार कर लिया गया।

गाजियाबाद। कौशांबी थाना क्षेत्र के भोवापुर से सात साल की बच्ची को पड़ोसी ने अगवा कर लिया। आरोपित ने कॉल कर पांच हजार रुपये की फिरौती मांगी। लोकेशन झांसी की निकली। इसमें झांसी पुलिस की मदद ली गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, कौशांबी के भोवापुर में कृष्णा गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं। उनकी सात साल की बच्ची लापता हो गई। स्वजन ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका पता नहीं चला। स्वजन ने कौशांबी थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। इसी बीच किराए पर पड़ोस में रहने वाले मदन ने कृष्णा गुप्ता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर पांच हजार रुपये की फिरौती मांगी।

पुलिस ने ऐसे किया बच्ची को बरामद

उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित की लोकेशन निकाली तो वह झांसी की आई। झांसी पुलिस से संपर्क किया गया। फिर पुलिस ने आरोपित को दबोचकर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

पहले ही निपटा लें सारा काम, 12 घंटे तक बाधित रहेगी बिजली की आपूर्ति

गाजियाबाद में रविवार को पटेलनगर प्रथम के 33/11 केवी उप केंद्र पर वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) बदलने का काम होगा। इससे आठ कॉलोनियों के पांच हजार से अधिक घरों में 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता ललित कुमार ने इस संबंध में शनिवार को सार्वजनिक सूचना जारी की है कि सुबह नौ बजे से लेकर सायं आठ बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

गाजियाबाद। गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उप केंद्रों को बेहतर बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। इसी क्रम में रविवार को पटेलनगर प्रथम के 33/11 केवी उप केंद्र पर वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) बदलने का काम होगा। इससे आठ कॉलोनियों के पांच हजार से अधिक घरों में 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

नगरीय विद्युत वितरण खंड सप्तम के अधिशासी अभियंता ललित कुमार ने इस संबंध में शनिवार को सार्वजनिक सूचना जारी की है कि सुबह नौ बजे से लेकर सायं आठ बजे तक इस केंद्र से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इन क्षेत्रों में पटेल नगर द्वितीय, शिब्बनपुरा, बौंझा,पटेलमार्ग, सेवानगर, उदलनगर, बाल्मीकि कुंज और दीनदयालपुरी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक परेशानी नगर निगम द्वारा की जाने वाली पेयजल आपूर्ति को लेकर होगी। सुबह सात बजे से पानी की आपूर्ति होती है।

लोगों ने बताया- बहुत परेशानी होगी

रविवार को अवकाश के चलते अधिकांश घरों में लोग 12 बजे तक नहाने, कपड़ा धोने और साफ सफाई का काम करते हैं। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से पानी की आपूर्ति ठप हो जाएगी। लोग परेशान होंगे। इसके लिए नगर निगम स्तर से पानी की आपूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। पटेल नगर स्थित बाल्मीकि कुंज के रहने वाले मुकेश जीनवाल का कहना है कि एक-दो घंटे बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर ही घरों में लोग परेशान होने लगते हैं। पहली बार 12 घंटे तक बिजली की आपूर्ति न किए जाने से बहुत परेशानी होगी।

अनुरक्षण माह में नहीं हुआ काम पूरा

शहरी क्षेत्र में बिजली के जर्जर तारों को बदलने, ट्रांसफार्मर बदलने, बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने और जर्जर खंभों को बदलने का काम अनुरक्षण माह में भी पूरा नहीं हुआ है। एक फरवरी से 29 फरवरी तक अनुरक्षण माह मनाया गया था। अधिकांश जगहों पर खंभा खड़ा करने के बाद संबंधित ठेकेदार तार लगाना भूल गए हैं।

योगीराज में साल दर साल सशक्त हुई मातृशक्ति, साकार हो रहा महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन का सपना

पिछले 07 वर्ष में योगी सरकार की नीतियों की समीक्षा करें तो 'महिला सशक्तिकरण' शासन की शीर्ष प्राथमिकता के रूप में साफ दिखाई देता है। रोजगार के लिए जो योजनाएँ शुरू की गईं, उसमें महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है।

महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ प्रदेश की योगी सरकार की कोशिशों के सकारात्मक नतीजे मिलने लगे हैं। स्वावलम्बन की बात करें तो पीरियॉडिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की महिला श्रम बल में भागीदारी दर 2017-18 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 32.10 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास किए गए, जिसके परिणामस्वरूप यह वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री की निजी तौर पर निगरानी ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही हैं, जो उन्हें अभूतपूर्व गति से आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80 प्रतिशत दर्ज की, जबकि उत्तर प्रदेश ने 32.10 प्रतिशत की दर दर्ज की. इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2017-18 में, भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 25.3 प्रतिशत थी, जबकि यूपी 14.2 प्रतिशत के साथ काफी पीछे था।

पिछले 07 वर्ष में योगी सरकार की नीतियों की समीक्षा करें तो 'महिला सशक्तिकरण' शासन की शीर्ष प्राथमिकता के रूप में साफ दिखाई देता है। रोजगार के लिए जो योजनाएँ शुरू की गईं, उसमें महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव-गांव में, गरीब परिवारों से भी नई-नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत पूरे देश मिले कुल ऋण में से लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। योगी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पूरक पुष्टाहार तैयार करने की जिम्मेदारी देकर न केवल संगठित भ्रष्टाचार से निजात दिलाई, बल्कि महिलाओं के एक बड़े वर्ग को आर्थिक स्वावलम्बन से भी जोड़ा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुणा बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानि 20 लाख की गई है। राज्य में 80 हज़ार राशन दुकानों में महिला स्वयं सहायता समूह की अहम भूमिका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और विविध आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण गरीबों को स्व-शासित संस्थानों में संगठित करती है। इस मिशन ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से सफल प्रगति की है और किसानों के रूप में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। सामुदायिक एकजुटता और महिलाओं की संस्थाओं के निर्माण के चरण से आगे बढ़ते हुए, अब ध्यान एसएचजी महिलाओं को उत्पादक समूहों, एफपीओ और निर्माता कंपनियों के माध्यम से उच्च क्रम की आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने पर है।

महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार की नीतियां पूरे देश में सराही जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध में सजा दिलाने में यूपी पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनकर उभरा है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकें, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी, वो सरकार ने हटाई है। देशभर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे, लड़कियों के लिए खोल देने का काम होना ऐतिहासिक है। बलात्कार जैसे संगीन अपराधों की तेज़ सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्थापित किए हैं।

बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि हाल ही में ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार कर दिया गया है। योजना से अब तक 18.66 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं। निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना संचालित है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ विधवा और तलाकशुदा भी उठा सकती हैं। एक जोड़े के विवाह पर कुल ₹51 हजार की धनराशि की व्यवस्था है। योजना के तहत अब तक 3.50 लाख जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। निराश्रित महिला को प्रति लाभार्थी ₹1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। वर्तमान में 31.50 लाख निराश्रित महिलाओं पेंशन दी जा रही है। जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता हेतु इस कोष की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत 7,105 महिलाओं/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की गई है। महिलाओं को संगठित, सशक्त, स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8.37 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को आच्छादित किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1,840 उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरित होने वाला पोषाहार अब स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किया जा रहा है। योगी सरकार की बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी योजना वित्तीय समावेशन का मॉडल बनकर उभरी है। जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामवासियों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने हेतु प्रदेश की सभी 57 हजार ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बी.सी. सखी को पदस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं की उत्तर प्रदेश में प्रगति

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: प्रदेश में 1.75 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। होली व दीपावली में निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: 'सबके लिए आवास' का संकल्प लिये यह योजना पात्र व्यक्तियों, खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश में 55.83 लाख आवास निर्मित किए गए हैं। इनमें अधिकांश आवास मातृशक्ति के नाम आंवटित किए गए हैं।

पी.एम. स्वनिधि योजना: प्रदेश में अब तक 17 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किया जा चुका है। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया है, जिससे उनके व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त हुआ है और जीवन में खुशहाली आई है।

स्वच्छ भारत मिशन: प्रदेश में अब तक 2.61 करोड़ शौचालयों (इज्जतघर) का निर्माण कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों में 4,500 पिंक शौचालय निर्मित कराए गए हैं।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (घरौनी): योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को अपनी जमीन का मलिकाना हक़ दिया जा रहा है, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज़ नहीं है। मलिकाना हक़ परिवार की महिला सदस्य के नाम अंकित किया जा रहा है। अब तक 66.59 लाख लाभार्थियों/महिलाओं को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: योजना के तहत अब तक 54.44 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना: योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 90 लाख महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

मिशन वात्सल्य योजना: प्रदेश में 75,811 बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया तथा 1,436 संभावित बाल विवाह रोके गये।

एक हजार सीसी की ताकत के साथ ये चार हैं सबसे बेहतर सुपर बाइक, जानें डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

सुपर बाइक कैटेगरी में दुनियाभर में कई बेहतरीन बाइक स कई कंपनियों की ओर से ऑफर की जाती हैं। कुछ लोग अपनी बाइक स को खरीदने के बाद मोडिफाई भी करवाते हैं। ऐसी कौन सी चार Top 1000cc Bikes हैं जिनको भारत में भी खरीदा जा सकता है। ये सुपर बाइक स किस तरह के फीचर्स के साथ आती हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल ली। देश में बड़ी संख्या में लोग बाइक चलाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को काफी महंगी और तेज रफ्तार सुपर बाइक्स का शौक होता है। भारतीय बाजार में किन कंपनियों की ओर से किस तरह के फीचर्स के साथ सुपर बाइक्स को ऑफर किया जाता है। हम इस खबर में आपको ऐसी Top 1000cc Bikes की जानकारी दे रहे हैं।

Ducati Panigale

डुकाटी की ओर से भारत में पैनिगेल वी4 को ऑफर किया जाता है। सुपर बाइक कैटेगरी में यह बाइक 1104 सीसी की क्षमता के लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। जिससे बाइक को 215.5 हॉर्स पावर के साथ 123.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें छह स्पीड क्विक शिफ्टर गियरबॉक्स मिलता है। इसमें बड़ी विंडस्क्रीन, कार्बन मडगार्ड, कार्बन हीलगार्ड, एबीएस कॉर्नरिंग ईवो, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल ईवो 3, स्लाइड एंड विली कंट्रोल, पावर लॉन्च, ईबीसी, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, डबल सायलेंसर, ब्रैम्बो ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 27.72 लाख रुपये से शुरू होती है।

BMW S1000RR

बीएमडब्ल्यू की ओर से एस1000आरआर को भी भारत में ऑफर किया जाता है। सुपर बाइक को 20.75 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। जबकि इसके प्रो एम स्पोर्ट वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 25.25 लाख रुपये है। इसमें 999 सीसी का ऑयल कूल्ड चार सिलेंडर फोर स्ट्रोक इन लाइन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 210 हॉर्स पावर के साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक की टॉप स्पीड 303 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। एस1000आरआर में हिल स्टार्ट कंट्रोल प्रो, एल्यूमिनियम फ्यूल टैंक, रेस एबीएस, ऑन बोर्ड कम्प्यूटर, रेन, रोड, डायनैमिक और रेस मोड, यूएसबी पोर्ट, यूएसडी फॉर्क्स, डायनैमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनैमिक ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रैशर कंट्रोल जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

Ninja ZX10r

कावासाकी भी इस सेगमेंट में निंजा जेडएक्स 10आर सुपर बाइक को ऑफर करती है। जिसमें 998 सीसी का लिक्विड कूल्ड फोर स्ट्रोक इनलाइन फोर इंजन मिलता है। जिससे बाइक को 213 पीएस की पावर और 114.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक में एलईडी लाइट्स, 4.3 इंच का डिजिटल कलर्ड इस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्रैम्बो ब्रेक, स्पोर्ट, रोड, रेन और राइडर मोड जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 16.63 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

Suzuki Katana

सुजुकी की ओर से भी भारतीय बाजार में कटाना सुपर बाइक को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस बाइक को जापान की फेमस तलवार कटाना के नाम पर नाम दिया गया है। बाइक में 999 सीसी का फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड डीओएचसी इनलाइन फोर इंजन दिया जाता है। इसके साथ ही छह स्पीड कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स मिलता है। 999 सीसी के इंजन से बाइक 152 हॉर्स पावर और 106 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक में मल्टी फंक्शन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी लाइट, फ्लोटिंग हैंडलबार, इंटेलीजेंट राइड सिस्टम, ड्राइव मोड सिलेक्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्ट सिस्टम, राइड बाय वायर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल सिस्टम, लो आरपीएम असिस्ट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 13.61 लाख रुपये है।

टॉप 10 कार: 5.54 लाख की Wagon R ने किया कमाल, जानें बिक्री के मामले में क या है टॉप-10 कारों का हाल

फरवरी 2024 के दौरान देशभर में करीब तीन लाख से ज यादा यात्री वाहनों की बिक्री हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 के दूसरे महीने में किस कंपनी की किस कार को सबसे ज यादा पसंद किया गया। बिक्री के मामले में Top 10 cars की लिस् ट में कौन कौन सी कंपनियों की कारों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में हर महीने बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री होती है। यात्री वाहन सेगमेंट में भी कारों की बिक्री काफी ज्यादा होती है। फरवरी 2024 के दौरान किस कंपनी की कार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही Top 10 cars की लिस्ट में किसके नाम शामिल हुए। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

मारुति वैगन आर

मारुति सुजुकी की Wagon R कार बीते महीने में सबसे ज्यादा भारतीयों की पसंद बनी। फरवरी 2024 में इस 5.54 लाख रुपये की इस कार ने अन्य सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 पोजिशन को अपने नाम किया। जानकारी के मुताबिक इस कार की कुल 19412 यूनिट्स की बिक्री फरवरी 2024 में हुई। जबकि फरवरी 2023 के दौरान इसकी कुल 16889 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

टाटा पंच

देश की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता Tata की Punch इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। इस माइक्रो एसयूवी की फरवरी 2024 के दौरान कुल 18438 यूनिट्स की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल फरवरी महीने में 11169 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

मारुति बलेनो

मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो को भी बीते महीने में काफी पसंद किया गया। नेक्सा डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली बलेनो की फरवरी 2024 में कुल 17517 यूनिट्स की बिक्री हुई। जबकि फरवरी 2023 में इस प्रीमियम हैचबैक को 18592 लोगों ने खरीदा था।

मारुति डिजायर

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की ओर से भी काम्पैक्ट सेडान के तौर पर डिजायर को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस बेहतरीन कार को बीते महीने में 15837 लोगों ने खरीदा। फरवरी 2023 में इस सेडान कार को 16798 लोगों ने खरीदा था।

अन्य कारों का हाल

टॉप-5 के साथ ही मारुति अर्टिगा इस लिस्ट में छठे नंबर पर रही। इस एमपीवी की कुल 15519 यूनिट्स बीते महीने में ग्राहकों ने खरीदीं। इसके बाद हुंडई की क्रेटा को 15276, महिंद्रा स्कॉर्पियो को 15051, टाटा नेक्सन को 14395 और मारुति फ्रॉन्क्स को 14168 ग्राहकों ने खरीदा।

यह है दुनिया की सबसे महंगी कार, कीमत 100-200 करोड़ नहीं बल्कि इससे भी कहीं अधिक

इस लग्जरी कार को सबसे अलग इसे बनाने में तैयार किया गया मैटेरियल है। Rolls Royce ने इसे तैयार करने के लिए सैंटोस स्ट्रेट ग्रीन शीशम हार्डवुड के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। जानकर दिलचस्प लगेगा कि इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वह अनोखी प्रजाति की लकड़ी है। इस कार को तैयार करने में रोल्स-रॉयस ने 8 हजार घंटे से भी ज्यादा समय लगाया है।

नई दिल्ली। लग्जरी कारों की कीमत करोड़ों में होती है ये अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन किसी कार की कीमत 250 करोड़ से भी ज्यादा हो तो आप यकीन करेंगे शायद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है क्योंकि हाल ही में रोल्स-रॉयस ने दुनिया की सबसे मंहगी कार पेश की है। जिसका नाम अर्काडिया ड्रॉपटेल (Arcadia Droptail) है। इसका नाम निर्माता के द्वारा ग्रीक शहर अर्काडिया से लिया गया है। आइए इस गाड़ी से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं।

सैंटोस स्ट्रेट ग्रीन शीशम हार्डवुड का हुआ है यूज

इस लग्जरी कार को सबसे अलग इसे बनाने में तैयार किया गया मैटेरियल है। Rolls Royce ने इसे तैयार करने के लिए सैंटोस स्ट्रेट ग्रीन शीशम हार्डवुड के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। जानकर दिलचस्प लगेगा कि इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वह अनोखी प्रजाति की लकड़ी है। इस कार को तैयार करने में रोल्स-रॉयस ने 8 हजार घंटे से भी ज्यादा समय लगाया है।

100-200 करोड़ से भी अधिक है कीमत

Rolls Royce अर्काडिया ड्रॉपटेल की कीमत 256.94 करोड़ रुपये है। इस कीमत के बाद यह दुनिया की सबसे मंहगी कार है। वहीं, इससे पहले भी दुनिया की सबसे महंगी कार बनाने का ताज रोल्स-रॉयस के पास ही था। बता दें इससे पहले रोल्स-रॉयस ला रोज नोयर ड्रॉपटेल थी, जिसकी कीमत 249.48 करोड़ रुपये है।

इंजन और टॉप स्पीड

अर्काडिया ड्रॉपटेल में 6.75 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड वी12 इंजन प्रदान किया गया है। यह पावरफुल इंजन 593 बीएचपी की शक्ति और 840 एनएम का टॉर्क निकालता है। गाड़ी महज 5 सेकंड में ही 100 किमी की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 22 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

Toyota Fortuner की मुश्किलें बढ़ाएंगी ये तीन SUV, जानें पूरी डिटेल

भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज यादा बिक्री होती है। ऐसे में कंपनियों की ओर से फुल साइज एसयूवी सेगमेंट पर भी ज यादा फोकस किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन अलग कंपनियों की ओर से जल द ही तीन एसयूवी को भारत लाया जा सकता है। कौन सी तीन Upcoming SUVs भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब ध हो सकती हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों से भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को पसंद किया जाता है। ऐसे में कंपनियों की ओर से इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा विकल्प ऑफर किए जाते हैं। फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में भी अब Toyota Fortuner की मुश्किल बढ़ने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बाजार में जल्द ही तीन नई SUV आ सकती हैं। किस कंपनी की ओर से किस एसयूवी को लाने की तैयारी हो रही है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

MG Gloster Facelift

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमजी की ओर से फुल साइज एसयूवी ग्लॉस्टर का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की योजना इस साल के मध्य में इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वेरिएंट को आधिकारिक तौर पर पेश करने की है। मौजूदा वेरिएंट के मुकाबले नए वेरिएंट में कंपनी कई कॉस्मैटिक बदलाव कर सकती है। जिसमें Projectors Headlamps, Panormic Sunroof और ADAS Level 2 के साथ ही कई नए फीचर्स को भी फेसलिफ्ट वेरिएंट में दिया जा सकता है। हालांकि इंजन के स्तर पर बड़ा बदलाव होने की संभावना कम है। फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर को फिलहाल एमजी की ग्लॉस्टर से ही चुनौती मिलती है।

Mitsubishi Pajero

जापान की वाहन निर्माता मित्सुबिशी भी भारतीय बाजार में अपनी वापसी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस साल में अपनी फुल साइज एसयूवी पजेरो के साथ भारतीय बाजार में मौजूदगी दर्ज करवा सकती है। कंपनी टीवीएस मोबिलिटी के साथ भारत में कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने करीब 26 साल पहले भारत में पहली बार अपनी कारों को पेश किया था। कंपनी पुरानी पजेरो के मुकाबले नई पजेरो में कई तकनीकी बदलावों के साथ ही कॉस्मैटिक बदलाव भी करेगी। इसके अलावा इसमें ADAS Level 2 जैसे सेफ्टी फीचर को भी दिया जा सकता है।

Ford Endeavour

अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड भी भारत में वापसी की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना के मुताबिक एंडेवर को भारत में एक बार फिर पेश किया जा सकता है। पुरानी एंडेवर को कंपनी नए फीचर्स और लुक्स के साथ ही एवरेस्ट नाम से लॉन्च कर सकती है। जिससे फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में अभी तक टोयोटा की फॉर्च्यूनर की बादशाहत को कड़ी चुनौती मिल सकती है। कंपनी ने कुछ समय पहले ही भारतीय बाजार में तीसरी पीढ़ी की Endeavour का डिजाइन पेटेंट रजिस्टर करवाया है।

रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 ग्राहकों को जमकर आ रही पसंद, लॉन्च के बाद कंपनी ने बेची इतनी यूनिट्स

कंपनी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस बाइक के लॉन्च होने के बाद से जनवरी 2024 के पहले हफ्ता तक इसकी कुल 6500 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के अर्निंग कॉल के दौरान बोलते हुए रॉयल एनफील्ड के सीईओ ने कहा कि ये प्रोडक्शन सभी नई पेशकशों के लिए ADV को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।

नई दिल्ली। रॉयल एनफील्ड की एडवेंचर टूरर जनरेशन में शामिल Royal Enfield Himalayan 450 को पिछले वर्ष नवंबर महीने में लॉन्च किया गया था। यह फीचर्स के मामले में काफी आधुनिक है इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन प्रदान किया गया है। हाल ही में इस बाइक की बिक्री को लेकर जानकारी मिली है। कहा गया है कि जनवरी 2024 तक इसकी 6,500 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

लॉन्च के बाद बिकी 6500 यूनिट

कंपनी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस बाइक के लॉन्च होने के बाद से जनवरी 2024 के पहले हफ्ता तक इसकी कुल 6,500 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के अर्निंग कॉल के दौरान बोलते हुए रॉयल एनफील्ड के सीईओ ने कहा कि ये प्रोडक्शन सभी नई पेशकशों के लिए ADV को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। निकट भविष्य में इसके लिए वैश्विक स्तर पर भी डिलीवरी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

नए प्लेटफॉर्म पर बनी है बाइक

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और उम्मीद है कि भविष्य में इसके और भी उत्पाद पेश किए जाएंगे। इसमें 450सीसी लिक्विड-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर 'शेपरा' इंजन प्रदान किया गया है। कहा गया है कि के-प्लेटफॉर्म के तहत आने वाली बाइक परफॉर्मेंस में और भी बेहतर होंगी। वहीं, जे-सीरीज छोटी और किफायती 350 सीसी रेंज को रेखांकित करना जारी रखेगी।

इंजन और फीचर्स

जैसा कि पहले बताया इसमें 450 सीसी लिक्विड-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर शेपरा इंजन प्रदान किया गया है जो 8,000 आरपीएम पर 39.4 बीएचपी की शक्ति और 5,500 आरपीएम पर 40 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस बाइक में 4 इंच के राउंड शेप टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्विचेबल एबीएस, गूगल मैप्स इंटीग्रेटेड नेविगेशन, राइड-बाय-वायर और 2 राइडिंग मोड (परफॉर्मेंस और ईको) जैसे फीचर्स को समायोजित किया गया है।

बॉन्ड बंद होने से चुनावों में बढ़ेगा काला धन

योगेंद्र योगी

चुनावी बॉण्ड के विवरण को सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार के साथ चंदा देने वाले उद्योगपतियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चुनावी बॉण्ड की खरीद के तहत सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है।

आज भाजपा सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है। यह निश्चित है कि केंद्र सरकार के चुनावों में काले धन के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट के बॉण्ड के मामले में दिए गए आदेश के बाद राजनीतिक दल फिर से चुनावी चंदे के नाम पर उद्योपतियों की बांह मरोडने से बाज नहीं आएंगे'

चुनावी बॉण्ड के विवरण को सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार के साथ चंदा देने वाले उद्योगपतियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। चुनावी बॉण्ड की खरीद के तहत सर्वाधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने वित्त वर्ष 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 1300 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा जुटाया है। यह राशि इसी अवधि में चुनावी बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को मिले चंदे की तुलना में सात गुना अधिक है। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड के जरिए 171 करोड़ रुपए की आय हुई जो वित्त वर्ष 2021-22 में 236 करोड़ रुपए से कम है। राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी को 2021-22 में चुनावी बॉन्ड के जरिए 3.2 करोड़ रुपए की आय हुई थी, लेकिन 2022-23 में उसे इन बॉन्ड के जरिए कोई धनराशि नहीं मिली। वहीं, राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त एक अन्य दल तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 34 करोड़ रुपए मिले जो पिछले वित्त वर्ष से 10 गुना अधिक राशि है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई के लिए बॉण्ड की जानकारी का खुलासा करना कोई बहुत कठिन काम हो। एसबीआई चाहे तो 24 घंटे में जानकारी को मुहैया करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अर्जी दाखिल करके बॉण्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक समय मांगा है। दरअसल इस बीच लोकसभा चुनाव सम्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद केंद्र की भाजपा सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले चुनावी बॉण्ड का खुलासा होने पर सर्वाधिक समस्या बॉण्ड के रूप में चंदा देने वाले उद्योगपतियों और व्यवसायियों को आई। भाजपा को चूंकि सर्वाधिक चंदा मिला है, ऐसे में बॉण्ड के खरीददार कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर रहेंगे। विशेषकर जिन राज्यों में कांग्रेस और गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, उनमें बॉण्ड खरीददारों को सत्तारूढ़ दलों के कोपभाजन का निशाना बनना पड़ सकता है। राजनीतिक दुर्भावना की नीयत से इनके खिलाफ कार्रवाई करने में विपक्षी दल कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी के नेता पहले ही अडानी और अंबानी को घेरे हुए हैं। यही वजह है कि एसबीआई गले पड़ी इस मुसीबत को टालने के लिए 30 जून तक का समय मांग रही है। इस अवधि के बाद केंद्र की भाजपा सरकार को किसी बात का डर नहीं रहेगा। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि फिर केंद्र में सरकार उसकी ही बनेगी। सरकार बनने के बाद भाजपा के बॉण्ड के खरीददारों को सुरक्षा देने में केंद्र सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। लेकिन इससे पहले यदि इनके नामों का खुलासा किया गया तो निश्चित तौर पर राज्यों के सत्तारूढ़ विपक्षी दल खरीददारों को बख्शेंगे नहीं। कारण स्पष्ट है कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस को बेहद कम और अन्य दलों को अल्पमात्र चंदा मिला है।

पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बॉण्ड के मूल्यवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वह इन बॉण्डों को जारी करना बंद कर दे और इस माध्यम से किए गए दान का विवरण चुनाव आयोग को दे। इसके बाद चुनाव आयोग से कहा गया कि वह इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि काले धन से लडने और दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने का घोषित उद्देश्य इस योजना का बचाव नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉण्ड काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका नहीं है। चुनावी बांड योजना 2018 में काले धन को राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश करने से रोकने के घोषित उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारंपरिक प्रथा नकद दान है। उन्होंने कहा था, 'स्रोत गुमनाम या छद्म नाम हैं।' धन की मात्रा का कभी खुलासा नहीं किया गया। वर्तमान प्रणाली अज्ञात स्रोतों से आने वाले अशुद्ध धन को सुनिश्चित करती है। यह पूरी तरह से गैर-पारदर्शी प्रणाली है। गोपनीयता खंड पर, उन्होंने कहा था कि दानदाताओं की पहचान का खुलासा उन्हें नकद विकल्प पर वापस ले जाएगा। दानकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने के लिए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉण्ड की खरीद और भुगतान के संबंध में देशभर में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (जहां से पहले इलेक्टोरल बॉण्ड जारी होते थे) के लिए एक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तय किया था। इसमें कहा गया था कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए इलेक्टोरल बॉण्ड खरीदने वाले के बारे में कोई भी ब्योरा यहां तक कि केवाईसी भी कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाली जाएगी। एसबीआई ने कहा है कि शाखाओं के जरिए खरीदे गए इलेक्टोरल बॉण्ड का ब्योरा केंद्रीयकृत ढंग से एक जगह नहीं रखा जाता। बॉण्ड खरीदने और उसके भुगतान की तिथि से जुड़ा ब्योरा दो भिन्न सिलोस में रखा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड का विवरण अब तक साझा नहीं किया है। इसकी डेडलाइन भी निकल चुकी है। स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय देने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक आवेदन में स्टेट बैंक ने दलील दी कि प्रत्येक साइलो से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने दाखिल किया है।

दरअसल, एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया करानी थी, लेकिन एसबीआई द्वारा यह जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और विपक्षी एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि जो पैसा बीजेपी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आपने इन पैसों से क्या किया? बीजेपी को अकेले 5000 करोड़ से ज़्यादा पैसा आया। एसबीआई इन तमाम बातों का खुलासा करे कि किस पार्टी ने कितना पैसा किसको दिया। इसके जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम अभी भी यह मानते हैं कि यह सबसे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था थी। अगर कोई कहता है कि बीजेपी को ज्यादा पैसा मिला तो यह कुतर्क है, आज से 30-40 साल पहले हम अगर कहते कि कांग्रेस को ज्यादा पैसा मिला तो उसका क्या मतलब था। आज बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है। यह निश्चित है कि केंद्र सरकार के चुनावों में काले धन के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट के बॉण्ड के मामले में दिए गए आदेश के बाद राजनीतिक दल फिर से चुनावी चंदे के नाम पर उद्योपतियों की बांह मरोडने से बाज नहीं आएंगे।

संपादक की कलम से

370 के बाद कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के साढ़े चार साल बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कश्मीर घाटी में गए, तो फिजाएं बदली हुई थीं। प्रधानमंत्री जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में जाते रहे हैं, लेकिन घाटी में पहुंचना उनके लिए भी चुनौती थी। बहरहाल अब 'जन्नत' का नैसर्गिक रूप खिल रहा है। कश्मीर घाटी मन और सोच से भाजपा-विरोधी रही है, लेकिन अब 'हम हिंदुस्तानी हैं', 'भारत माता की जय' के नारे बुलंद थे। असंख्य लोगों को एक स्वर में उद्घोष करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अक्सर राजनीतिक जनसभाएं प्रायोजित होती हैं, भीड़ को लाया जाता है, लेकिन टीवी चैनलों पर आम कश्मीरी के बोल सुने, तो एकबारगी लगा कि कश्मीर अब खुलकर सांस लेने लगा है। आतंकवाद की घटनाओं में 73 फीसदी की कमी आई है। नागरिकों की मौतें 81 फीसदी तक कम हुई हैं। अलगाववाद का खात्मा इसी से साफ है कि अब घाटी में दुकान, बाजार, फैक्टरी, स्कूल-कॉलेज आदि को बंद कराने वाली आवाजें खामोश हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं 'शून्य' हैं। शारदा मंदिर में इस बार दीपावली मनाई गई। सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। दलितों, स्थानीय समुदायों को आरक्षण मिला है और महिलाओं के संवैधानिक अधिकार बहाल किए जा चुके हैं। कश्मीरी महिलाएं अपना जीवन-साथी 'गैर कश्मीरी' को भी चुन सकती हैं। औरतों को संपत्ति खरीदने की आजादी है। अब उनकी पैतृक संपत्ति में भी हिस्सेदारी तय है।

अब कश्मीर में जी-20 की बैठकें हुईं, तो विदेशी प्रतिनिधियों ने नए कश्मीर को देखा और आनंद लिया। बीते साल 2 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर की हसीन, खूबसूरत वादियों का सुख लेने आए, तो सरकार ने 30 सालों के लिए पीपीपी मॉडल पर अपनी 11 संपत्तियों को आउटसोर्स करने की योजना बनाई। होमस्टे पर खास जोर दिया जा रहा है। चूंकि लोगों की आवाजाही खुली और बढ़ी है, तो डल झील का नूरानी सौंदर्य भी लौट आया है। कश्मीरी पश्मीना शॉल, साडियों और सलवार-कमीज जैसे वस्त्रों का निर्यात बहाल हुआ है। कश्मीरी कहवा और केसर के निर्याती बाजार भी खुल चुके हैं। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था फलने-फूलने लगी होगी। कश्मीर घाटी अब देश की मुख्यधारा से जुड़ कर अनुच्छेद 370 का इतिहास और अतीत भूल चुकी है। किसी पारिवारिक सियासत का हिस्सा 370 अब भी होगा, लेकिन आम कश्मीरी का कोई विरोध नहीं है। उसे सिर्फ विकास और रोजगार की दरकार है। वह इससे खुश और देश से जुड़ा महसूस करता है कि 53 विकास योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने घाटी में किया। गांव-गांव तक 10 फुट की सडक़ें बन रही हैं। करीब 25,000 खिलाडियों ने खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। कई खिलाड़ी तो राष्ट्रीय टीमों के सदस्य हैं। करीब 15 लाख परिवारों को 'पानी' मुहैया कराया गया। सबसे अहम यह है कि राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' फिजाओं में लहरा रहा है और भारत का संविधान, संसद द्वारा पारित किए गए कानून अब जम्मू-कश्मीर में भी प्रभावी और प्रासंगिक हैं। कश्मीर में दो एम्स खुल चुके हैं, जाहिर है कि स्वास्थ्य भी सरकार के लिए अहम सरोकार है। ये तमाम उपलब्धियां और बदलाव एक ही दौर की देन नहीं हैं और न ही किसी व्यक्ति-विशेष से जुड़ी हैं। यह बीते 10 साल का यथार्थ है, जो कश्मीर में अब मूर्त रूप ले रहा है। बेशक इनकी सूत्रधार भारत सरकार रही है और सर्वोच्च अदालत ने भी दखल देकर 370 की पेचीदगियों को खोला है। प्रधानमंत्री मोदी भी श्रेय के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसी योजनाएं बनवाईं और उन्हें लागू करवाया। हालांकि आतंकवाद अब चंद इलाकों में सिमटा है।

चर्चा

हड़ताल से रैगिंग तक डाक्टर

या तो यहां नक्शा बड़ा था, या हमने उसे पढ़ा नहीं। हिमाचल में जो डाक्टर बन गए, वे हड़ताल के सुपुर्द हैं और जो बन रहे हैं, उनकी गलियों में कीचड़ भरा है। शुरू डाक्टरों की हड़ताल से करें या नाहन मेडिकल कालेज के ब्लैक बोर्ड पर रैगिंग का पाठ पढ़ें। दोनों ही परिस्थितियों में गुणात्मक दृष्टि से ये उदाहरण असहज करते हैं। नाहन के मेडिकल कालेज ने ऐसे प्रशिक्षु डाक्टर बना दिए जिन्होंने गंभीर पाठ्यक्रम से रैगिंग का विषय चुरा लिया। जूनियर डाक्टरों के साथ व्यावहारिक तौर पर जो हुआ, उसके कारण भले ही नौ प्रशिक्षु डाक्टरों पर त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल यह कि हम काचरू कांड के बाद भी शिक्षण संस्थानों को इस तरह की बेहूदगी से सुरक्षित नहीं रख पाए। इसके कारणों को समझने के लिए जांच केवल घटनाक्रम पर अटक जाती है, जबकि उन फैसलों पर तवज्जो देनी चाहिए जो सत्ता के दम पर संस्थानों और सियासी चबूतरों में अंतर नहीं समझती। नाहन मेडिकल कालेज का निर्माण और अस्तित्व दोनों ही शहर की तंग गलियों में फंसे हैं। जहां शायद एक बेहतरीन अस्पताल भी अपने पांव पसारने से गुरेज करता, वहां मेडिकल कालेज की दीवारें अपने ही अस्तित्व से द्वंद्व कर रही हैं। यह राजनीतिक सोच की दुर्घटना क्यों न मानी जाए कि अब हर क्षेत्रवाद की उपज से संस्थान बर्बाद हो रहे हैं। प्रदेश अब न समग्रता से गतिशील है और न ही प्रगतिशील है, बल्कि ऐसे संस्थानों को चरागाह बनाया जा रहा है। यहां भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना किसी पर्यटन स्थल पर नहीं होती, जबकि कृषि उत्पादक क्षेत्रों से दूर कहीं कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसी तरह जब निजी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खुले तो एक ही पंचायत क्षेत्र में आधा दर्जन खुल गए। सोलन को बनाने तो चले थे शिक्षा का हब, लेकिन राजनीतिक प्राथमिकताओं ने शिक्षा के परचे ही फाड़ दिए। नतीजतन कई शटर बंद होने के कगार पर हैं। यही द्वंद्व केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर और परिचय को लेकर अगर धूमल सरकार के दौर से शुरू हुआ, तो सुक्खू सरकार आने तक भी प्रश्नांकित है। हमने शिक्षा को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के ताने बाने में फंसा कर छात्रों के वास्तविक करियर को ही लावारिस बना दिया। अब हर कालेज को स्नातकोत्तर बनाने की होड़ में उपलब्धियां तो रैगिंग सरीखी ही होंगी। आश्चर्य यह कि कांगड़ा के थुरल जैसे कालेज की जमीन पर बाढ़ का कब्जा हो जाता है, तो मटौर का सारा कालेज सडक़ पर क्लास लगाता है। शिक्षा में करियर की तलाश के लिए हमारे पास अगर संस्थान नहीं होंगे, तो इन परिसरों की अनिश्चितता छात्रों को असंवेदनशील ही बनाएगी। हिमाचल में पहले निजी विश्वविद्यालयों के अलावा डेढ़ दर्जन इंजीनियरिंग कालेजों ने छात्रों से तौबा की, तो अब मेडिकल कालेजों से हर साल आठ सौ के करीब तैयार होने वाले डाक्टर आखिर कहां जाएंगे। जीने और आगे बढऩे की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन अगर नाहन मेडिकल कालेज में करें, तो हिमाचल का सूचकांक समझ आ जाएगा और अगर डाक्टरों के प्रोफेशन को अस्पतालों में पसरे संघर्ष के माहौल में देखें तो अस्थिरता के मजमून समझ आएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में राज्य की तस्वीर के गुणात्मक पहलू नदारद हैं, तो असंवेदनशीलता के बीच न तो सरकार का पक्ष और न ही नागरिक समाज की भूमिका दिखाई देती है। इस दौरान एक अलग तरह का व्यापारवाद फैल रहा है। यानी निजी अस्पताल अपने विकल्प में सरकारी डाक्टरों से विश्वसनीयता छीन रहे हैं, तो यह परिस्थिति असंतुलन पैदा कर रही है।

संस्कृति पर मंडराते संकट के बादल

प्रताप सिंह पटियाल

बर्तानिया हुकूमत का सूर्यास्त होने के बाद यदि हिंदोस्तान के फलक पर मगरिब के बादल मंडरा रहे हैं तो इस तहजीब की वजाहत में बालीवुड ने एक मखसूस किरदार अदा किया है। भारतीय संस्कृति व संस्कारों को दूषित करने वाली पश्चिमी तहजीब सिनेमा के जरिए ही सामाजिक परिवेश में दाखिल हुई है'

'जलेष्मेव जयमहे' अर्थात जल में जीतना चाहिए। संस्कृत का यह ध्येय वाक्य विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी में शुमार करने वाले देश इंडोनेशिया की नौसेना का है। 'बुद्धि सर्वत्र भ्राजते' यानी बुद्धि सर्वत्र प्रकाशमान होती है। यह आदर्श वाक्य श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय का है। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक 'गरुड़' है। कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति व परंपराओं से कितनी मोहब्बत करता है, थाईलैंड व इंडोनेशिया इसका उदाहरण हैं। दोनों देशों में अलग-अलग मजहब होने के बावजूद वहां के लोगों ने अपने पूर्वजों की हजारों वर्ष पुरानी सनातन संस्कृति का त्याग नहीं किया। इतिहास साक्षी है कि अपनी तहजीब को भूलने व विरासतों को नजरअंदाज करने वाले मुल्कों को अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है। भारत का हमसाया मुल्क पाकिस्तान इसका उदाहरण है। अनादिकाल से ज्ञान व विज्ञान के शिखर को छूने वाला भारत अपने दार्शनिकों द्वारा स्थापित मानवता के सिद्धांतों तथा ऋषियों द्वारा रचित वैदिक साहित्य व आध्यत्मिक ज्ञान संपदा का वारिस रहा है। भारत के महान विचारकों व विद्वानों द्वारा स्थापित सिद्धांतों की बुनियाद पर ही भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक सुरक्षित है। हिंदोस्तान की सरजमीं से बर्तानिया बादशाही का निजाम सात दशक पूर्व रुखसत हो गया, परंतु पश्चिमी तहजीब व अंग्रेजों की कई रिवायतें भारत में आज भी कायम हैं। युवा वर्ग से लेकर उम्रदराज लोगों तक पश्चिमी तहजीब का खुमार हावी हो चुका है। भारतीय समाज की विविध परंपराओं, भाषा, खानपान, लिबास तथा शिक्षा व्यवस्था तक अंग्रेजी संस्कृति का वर्चस्व कायम हो चुका है। रोजमर्रा की कई विदेशी चीजें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं।

विदेशी कंपनियां देश के बाजारों को अपनी जद में ले चुकी हैं। विदेशी कोचों के बिना देश की खेल व्यवस्था अधूरी रहती है। जन्मदिन से लेकर शादी समारोह, शादी सालगिरह व त्योहारों तक विदेशी तहजीब की झलक देखने को मिलती है। मधुशालाओं में सजी शीशे की बोतलों में अंगड़ाई लेती आब-ए-तल्ख विदेशी कंपनियों की है। कई होटलों में नौजवानों का खैरमकदम करने वाली हुक्का बारों की नशीली महफिल तथा अमीरों के शहजादों से सजी व महंगे नशे के लिए कुख्यात रेव पार्टियों की बज्म-ए-अंजुम मगरिब की बेगैरत तहजीब का आईना है। इश्क-ओ-मोहब्बत का इजहार करने के लिए मगरिब की रंगत में रंगा वेलेंटाइन डे अजीब किस्म के लुत्फ से मनाया जाता है। मुल्क के निजाम पर हुक्मरानी करने वाली अफसरशाही की फितरत, नजरिया व शौक अंग्रेजों वाले हैं। पर्यटकों तथा बालीवुड के अदाकारों के लिए शूटिंग का लोकप्रिय डेस्टिनेशन पश्चिमी देश हैं। पश्चिमी संगीत के आगे पारंपरिक लोकगीतों व वाद्ययंत्रों की सरगम लुप्त हो रही है। शास्त्रीय संगीत अपने वजूद को तलाश रहा है। विदेशी खानपान के बढ़ते प्रचलन से पारंपरिक खाद्य व्यंजनों की लज्जत फीकी पड़ रही है। नववर्ष का जश्न अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही मनाया जाता है। समाज को सभ्य व संस्कारी बनाने के लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने कई नियम, सिद्धांत व मर्यादाएं तय की थीं। हजारों वर्ष पूर्व तत्वज्ञानी आचार्य महर्षि 'श्वेतकेतु' ने कड़े परिश्रम से सनातन धर्म में विवाह संस्कार का मसौदा तैयार किया था। भारतवर्ष की घोषा, अपाला, सूर्या सावित्री, सुवर्चला व ब्रह्मवादिनी विश्ववारा जैसी विदुषी ऋषिकाओं ने भी विवाह प्रणाली की स्थापना के लिए वैदिक विवाह परंपरा को विधिवत स्वरूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन विडंबना है कि मनुष्य के पुरुषार्थ व चरित्र निर्माण में अहम संस्कारों की बुनियाद रखने वाले सनातन के ध्वजवाहक महान आचार्य व ऋषिकाएं भारतीय इतिहास से गुम हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार से अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे व सात वचनों से सम्पन्न सात जन्मों तक का बंधन निभाने वाले दिव्य संस्कार विवाह को अनुबंध के तौर पर माना जाने लगा है। संगीन जुर्म व अभद्रता का पर्याय बन चुकी लिव इन रिलेशनशिप तथा सभ्य समाज के लिए नामंजूर समलैंगिक विवाह जैसी बेमुरब्बत कुरीतियां पश्चिम की देन हैं। कन्या पूजन वाले देश भारत में बालिकाश्रम व अनाथालयों की संख्या बढ़ रही है। परिवार

की शान रहे बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम में कयाम अंग्रेजी तहजीब का ही आयाम है। हालांकि जीवन में घनिष्ठ संबंध रखने वाले भारतीय संस्कृति के कई संस्कार वैश्विक स्तर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई देशों में लोग स्वस्थ रहने के लिए ऋषियों की विरासत योग, आयुर्वेद व शाकाहारी भोजन को अपनाकर भारतीय संस्कृति का अनुकरण बड़े अदब से कर रहे हैं। मानसिक शांति के लिए भारतीय दर्शन का अध्ययन व आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'ऋषि सुनक' भारतीय संस्कृति को पूरी निष्ठा से अपनाते हैं।

गत आठ फरवरी को पश्चिमी आस्ट्रेलिया से निर्वाचित भारतीय मूल के सांसद बैरिस्टर 'वरुण घोष' ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में 'श्रीमद्भगवदगीता' पर हाथ रखकर शपथ लेकर विदेशी भूमि पर भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया। लेकिन भारत में सेकुलरवाद का नकाब धारण कर चुकी मौकापरस्त सियासत के चलते सभी भाषाओं की जननी संस्कृत तथा जगत प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति अपने ही देश में उपेक्षित हो रही है। बर्तानिया हुकूमत का सूर्यास्त होने के बाद यदि हिंदोस्तान के फलक पर मगरिब के बादल मंडरा रहे हैं तो इस तहजीब की वजाहत में बालीवुड ने एक मखसूस किरदार अदा किया है। भारतीय संस्कृति व संस्कारों को दूषित करने वाली पश्चिमी तहजीब सिनेमा के जरिए ही सामाजिक परिवेश में दाखिल हुई है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बेपरवाह बालीवुड भारतीय संस्कृति को आईना दिखाने से गुरेज नहीं करता। बहरहाल हजारों वर्ष पुराने लिखित साक्ष्यस्वरूप 'यजुर्वेद' के अनुसार 'सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा' अर्थात यह प्रथम संस्कृति है जो विश्वव्यापी है। अतः अपनी संस्कृति व संस्कारों पर गर्व होना चाहिए। अपनी महान संस्कृति को दरकिनार करके विदेशी तहजीब की नुमाइश करना आधुनिकता नहीं है।

छिलकों की छाबड़ी : मैं तटस्थ आदमी हूं भाई

कृपया मेरा नाम किसी के साथ न जोड़ा जाए। न तो मैं सीधी तरह उधर हूं और न ही सीधी तरह इधर हूं। मैं बीच में हूं और समय की धार देख रहा हूं। आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं तटस्थ आदमी हूं। लेकिन मेरी नजर बराबर दोनों तरफ है। जिस तरफ पलड़ा भारी होगा, उस तरफ चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं पूरी तरह किसी के साथ नहीं हूं। यह बात या तो ईश्वर जानता है या फिर मेरी वाइफ जानती है। दोनों को मालूम है कि मैं हवा का रुख देखकर ही अपना स्टैंड लेता हूं। ईश्वर और वाइफ के अलावा कोई तीसरा आदमी मेरे बारे में गारंटी से कुछ नहीं कह सकता। अगर कहेगा भी तो पब्लिक उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करेगी। पब्लिक को मालूम है कि हम कोई ऐरे गैरे, नाथू खैरे किस्म के नहीं, बल्कि तटस्थ किस्म के आदमी हैं। पब्लिक ने कई बार अपनी आंखों से ऐसा देखा भी है। विभिन्न राजनीतिक दलों की जनसभा में भी अपुन तटस्थ रहते हैं। तटस्थ होकर ही उनकी दावतों में जाते हैं। मुर्ग मुसल्लम उड़ाते हैं और दारू पीकर घर आ जाते हैं। डकार तक नहीं मारते। कोई डींग भी नहीं मारते। अपुन तटस्थता के मामले में बापू के तीन बंदरों की तरह है, यानी अपुन ने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं बोला। चुनावों के दिनों में अपुन कुछ ज्यादा ही तटस्थ हो जाते हैं। कोई प्रत्याशी दारू की पेटी घर पर भिजवाता है तो तटस्थ भाव से उसे ग्रहण करते हैं। कोई कीमती तोहफा भिजवाता है तो उसे भी तटस्थता से ले लेते हैं। 'थैंक्स' कहकर अपुन आचार संहिता की अवहेलना नहीं करते। तटस्थ रहकर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और मन ही मन भगवान से यह दुआ करते हैं कि ऐसा मौका 5 साल में एक बार नहीं बल्कि बार-बार आए ताकि हम बार-बार गौरवान्वित होने की फीलिंग ले सकें। इससे बढक़र पब्लिक को हमारे तटस्थ होने का सबूत क्या मिल सकता है कि जब कोई मनचला किसी अबला पर फब्तियां कस रहा होता है या कोई गुंडा किसी निरीह आदमी को बेवजह पीट रहा होता है तो अपन चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। जब हम हैं ही तटस्थ तो फिर बेवजह पंगा काहे को लें। जब शहर में दंगा होता है तब भी तटस्थ रहते हैं और जब दंगे के बाद राहत बंटती है, तब भी तटस्थ भाव से लाइन में खड़े हो जाते हैं, चाहे नुकसान हुआ हो या नहीं। जैसे सांप्रदायिक दंगा करवाने के बाद लीडर धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। तटस्थ होकर अपुन अपनी राष्ट्रीय परंपराओं का निर्वहन करते हैं। जैसे भारत गुट-निरपेक्ष देश है, इस तरह अपुन भी गुट-निरपेक्ष आदमी हैं। गुट निरपेक्ष यानी तटस्थ। न इसके साथ, न उसके साथ। न इस लफड़े में, न उस पचड़े में। तटस्थ होने के फायदे भी बहुत हैं। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हमेशा तटस्थ रहता है। इसलिए फायदे में रहता है। बकौल डार्विन बंदर चूंकि अपुन का पूर्वज भी है, इसलिए अपुन को गर्व है कि अपुन अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तटस्थ होने के फायदे बहुत हैं। दोनों तरफ संपर्क बना रहता है। दोनों पक्षों के लोग हमें अपना ही समझते हैं और जिसका पलड़ा भारी रहता है, उसे हम चुपचाप जाकर बधाई दे आते हैं। दूसरे पक्ष के पास जाकर सांत्वना व्यक्त कर आते हैं। गुडविल दोनों की ले लेते हैं। मौजूदा स्थिति में भी अपुन इसी राह पर चले हैं। न तो सीधी तरह इसके साथ है और न ही सीधी तरह उसके साथ। इसलिए मेरा नाम किसी के साथ न जोड़ा जाए। मैं अपनी शानदार छवि को दागदार नहीं करना चाहता।

गुरमीत बेदी

"विभिन्न राजनीतिक दलों की जनसभा में भी अपुन तटस्थ रहते हैं। तटस्थ होकर ही उनकी दावतों में जाते हैं। मुर्ग मुसल्लम उड़ाते हैं और दारू पीकर घर आ जाते हैं। डकार तक नहीं मारते। कोई डींग भी नहीं मारते। अपुन तटस्थता के मामले में बापू के तीन बंदरों की तरह है, यानी अपुन ने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं बोला।

15 मार्च का इंतजार मत कीजिए, पेटीएम फास्टैग से अभी छुटकारा पाने में भलाई, जानें बंद करने से रिफंड पाने तक पूरा प्रोसेस

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जारी किए फास्टैग 15 मार्च के बाद काम करना बंद कर देंगे। फास्टैग में ना तो सिम कार्ड की तरह पोर्ट कराने की सुविधा होती है और ना ही क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने की। ऐसे में आपके पास इकलौता विकल्प पेटीएम फास्टैग को बंद करना ही है। फास्टैग में बची रकम कैसे मिलेगी? फास्टैग को बंद करने के लिए क्या करना होगा? आइए जानते हैं

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर जोड़ने से प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय बैंक ने यह भी कह दिया कि वन97 कम्युनिकेशंस के मालिकाना हक वाला यह बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद कोई कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड कार्ड, पेटीएम वॉलेट और फास्टैग में क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप नहीं कर पाएगा। RBI के फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वे लोग हैं, जिन्होंने पेटीएम के फास्टैग (FASTag) ले रखे हैं। केंद्रीय बैंक के आदेश में स्पष्ट है कि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जारी किए FASTags में कोई फंडिंग या टॉप-अप नहीं किया जा सकता। मतलब कि किसी और बैंक या वॉलेट का इस्तेमाल करके भी आप इन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते।

आइए जानते हैं कि अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का FASTag है, तो आपको क्या करना चाहिए?

क्या पेटीएम फास्टैग बंद कर देना चाहिए?

बिल्कुल। पेटीएम फास्टैग तो बंद करने में बिल्कुल देरी ना करें। खासकर, अगर कोई रकम नहीं बची है क्योंकि अब आप उसे रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। फास्टैग में ना तो सिम की तरह पोर्ट कराने की सुविधा है और ना ही क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करने की।

ऐसे में आपके पास इकलौता विकल्प पेटीएम फास्टैग को बंद करना ही है। अगर उसमें कोई रकम बची है, तो आपको बैंक से रिफंड के लिए अनुरोध करना होगा। असुविधा से बचने के लिए आपको 15 मार्च से पहले किसी अन्य ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से नया फास्टैग ले लेना चाहिए।

पेटीएम फास्टैग तुरंत बंद करना जरूरी क्यों?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग बंद करने में कम से कम 5-7 दिन लगते हैं। आप जैसे अकाउंट बंद करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, तो आपको यह मैसेज मिलेगा, 'आपका फास्टैग 5-7 वर्किंग डेज में बंद हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट समेत आपकी बकाया रकम आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में वापस कर दी जाएगी।'

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि 10 से ज्यादा दिन बीतने के बाद भी उनका पेटीएम फास्टैग बंद नहीं हुआ है। ऐसे में आप जितना जल्दी बंद करने की रिक्वेस्ट डालेंगे, उतना ही सही रहेगा। साथ ही, आप पेटीएम फास्टैग को बंद करने के बाद ही नया फास्टैग ले सकते हैं।

Paytm App से Paytm FASTag बंद करने का तरीका:

- पेटीएम अकाउंट में लॉगिन कर 'FASTag' सर्च करें।
- 'मैनेज FASTag' विकल्प चुनें।
- फिर होम पेज पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और 'हेल्प एंड सपोर्ट' चुनें।
- 'नीड हेल्प विद नॉन-ऑर्डर रिलेटेड क्वेरीज' सेलेक्ट करें।
- 'आई वांट टू क्लोज माय फास्टैग' चुनें और कन्फर्म करें।
- यहां FASTag अकाउंट करने का कारण सेलेक्ट करें।

बैंक कर्मचारियों के वेतन में होगी सालाना 17 प्रतिशत की वृद्धि

भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार को 17 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति बनी। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सालाना 8284 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बीच ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) ने कहा कि महीने के सभी शनिवार को छुट्टियों के रूप में मंजूरी देने पर भी सहमति जताई गई है।

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। नवंबर 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब आठ से लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार को 17 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि पर सहमति बनी।

बीमारी की छुट्टी लेने की होगी अनुमति

इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सालाना 8,284 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बीच ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) ने कहा कि महीने के सभी शनिवार को छुट्टियों के रूप में मंजूरी देने पर भी सहमति जताई गई है। हालांकि कामकाज के घंटों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा।

नए वेतन समझौते के तहत सभी महिला कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र दिए बगैर हर महीने एक दिन की बीमारी की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि संचित विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) को सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर 255 दिनों तक भुनाया जा सकता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में इस बात पर सहमति बनी है कि मासिक अनुग्रह राशि का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भुगतान की जाने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त किया जाएगा। यह राशि उन पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को मिलेगी जो 31 अक्टूबर 2022 या उससे पहले पेंशन प्राप्त करने के पात्र बन गए हैं। उस तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी इसके दायरे में आएंगे।

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमैन क्या है, इससे आसान कैसे हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जानें पूरी डिटेल्स

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय कई लोगों को अपनी पिछली डिटेल याद नहीं रहती। इससे उन्हें ITR फाइल करने में दिक्कत होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Annual Information Statement लाया था। इसमें आपके पैन आधार और पते के साथ रिफंड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। साथ ही अगर डिपार्टमेंट ने आपसे कोई जानकारी मांगी है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना कई लोगों को पेचीदा काम लगता है। इसकी बड़ी वजह है कि उन्हें टैक्स से जुड़े नियम-कानून और दस्तावेजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती। साथ ही, वे अपनी टैक्स फाइल (Income Tax Declaration) से जुड़ी डिटेल भी भूल जाते हैं।

लेकिन, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement-AIS) के बारे में पता है, तो आपकी कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं।

इस सुविधा को नवंबर 2021 के पेश किया गया था। यह टैक्सपेयर्स की उन जानकारियों के बारे में बताता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से होती हैं। आइए AIS के बारे में सबकुछ विस्तार से जानते हैं।

क्या होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट?

इस स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जरूरी सभी जानकारियां भी शामिल होती हैं। इस फॉर्म में टैक्सपेयर्स की जानकारियां दो हिस्सों में होती हैं।

पार्ट A : इस हिस्से में करदाता की सामान्य जानकारियां होती हैं। जैसे कि पैन, मास्क्ड आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, एड्रेस, नाम और जन्म की तारीख। अगर इंडिविजुअल की जगह कोई कंपनी है, तो जन्म की जगह उसकी स्थापना वाली तारीख की जानकारी होती है।

पार्ट B : इसमें आपके टैक्स से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दिखती हैं।

SFT की जानकारी : यहां स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) करने वाली कंपनियों से मिली जानकारी होती है। इसमें कंपनियों से मिला डिविडेंड और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल रहता है।

डिमांड और रिफंड : इस सेक्शन से आपको यह पता चल जाता है कि किसी वित्त वर्ष में आपको कितना रिफंड जारी हुआ और आपसे किन जानकारियों डिमांड हुई थी।

अन्य जानकारियां: इस हिस्से में अन्य स्रोतों से मिली इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं। मसलन- सैलरी का एनेक्सचर II फॉर्म, रिफंड पर मिलने वाला इंटरेस्ट, विदेशी मुद्रा की खरीदारी।

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) कैसे डाउनलोड करें:

- इनकम टैक्स की ऑफिशियल सा इ ट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- PAN/आधार और पासवर्ड से ITR फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड मेनू पर AIS ऑप्शन दिखेगा, वहां Proceed पर क्लिक करें।
- आप सीधे AIS पोर्टल (ais.insight.gov.in/complianceportal) पर पहुंच जाएंगे।
- डिटेल देखने के लिए AIS पर क्लिक करें।

आप इसे PDF या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

इन स्कीमों में पैसा लगाकर टैक्स बचा सकते हैं सीनियर सिटीजन, तगड़ा रिटर्न भी मिलेगा

परिवहन विशेष न्यूज

सीनियर सिटीजन अक्सर रिटायरमेंट का ऐसी स्कीमों में पैसा लगाना चाहते हैं जो उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न दें साथ ही टैक्स (Senior Citizen Tax Saving) भी बचाएं। उम्र की इस दहलीज पर वे लंबा लॉक-इन पीरियड भी नहीं चाहते। ऐसे में हम आप कुछ स्कीमों के बारे में बता रहे हैं जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं

नई दिल्ली। वरिष्ठ नागरिकों को अमूमन रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त अच्छी खासी रकम मिलती है। ऐसे में उन्हें ऐसे विकल्पों की तलाश रहती है, जो उनके निवेश पर अच्छा विकल्प दें। साथ ही, टैक्स बचत भी कराएं। लेकिन, उम्र की इस दहलीज पर वे लंबी अवधि की स्कीमों का भी रुख नहीं करना चाहते।

ऐसे में हम सीनियर सिटीजन के लिए कुछ स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जो अच्छा रिटर्न देने के साथ टैक्स (Senior Citizen Tax Saving) भी बचाती हैं और इनमें लॉक-इन पीरियड भी अधिक नहीं होता।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी जाती है। इसमें फिलहाल 8.2 फीसदी ब्याज मिलता है और सरकार ने अगली तिमाही के लिए भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। 1.50 लाख रुपये के निवेश पर 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। निवेश की लिमिट 30 लाख रुपये है। आपका इन्वेस्टमेंट पांच साल में मैच्योर होता है, जिसे आप 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)

म्यूचुअल फंड की इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश सिर्फ 3 साल के लॉक रहता है। डेढ़ लाख रुपये तक के सालाना निवेश पर 80सी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। हालांकि, ELSS स्कीम के साथ जोखिम भी जुड़ा रहता है। इस स्कीम के पैसों को म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में लगाते हैं। ऐसे में रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट आती है, तो नुकसान भी हो सकता है।

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (TSFD)

सभी बैंक में टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम होती है। यह काफी सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसमें भी सालाना डेढ़ लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। अगर ब्याज दर की बात करें, तो यह पूरी तरह से बैंकों और निवेश की अवधि पर निर्भर होता है। ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज ऑफर करते हैं। सीनियर सिटीजन को अमूमन आम ग्राहकों की तुलना में TSFD पर अधिक ब्याज दर मिलती है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)

इस योजना के जरिए भी सीनियर सिटीजन टैक्स बचा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज दर फिलहाल 7.7 फीसदी है। इसमें लॉक-इन पीरियड पांच साल का है, यानी अगर आप पांच साल से खाता बंद करा देते हैं, तो आपको सिर्फ निवेश वाली रकम मिलेगी, ब्याज वाले पैसे नहीं। इसमें भी डेढ़ लाख रुपये तक के सालाना निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

चार यूरोपीय देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार भारत, इस दिन समझौते पर लगेगी मुहर

चार देशों के यूरोपीय समूह EFTA और भारत वस्तुओं सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों समूह जनवरी 2008 से व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर बातचीत कर रहे हैं। ईएफटीए के कनाडा चिली चीन मैक्सिको और कोरिया सहित 40 भागीदार देशों के साथ 29 एफटीए हैं।

नई दिल्ली। भारत और चार देशों के यूरोपीय समूह 'EFTA' वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस समझौते को सात मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। ईएफटीए देश यूरोपीय संघ (ईयू) का हिस्सा नहीं हैं। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना उन देशों के लिए एक विकल्प के रूप में की गई थी, जो यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते थे।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते

भारत और ईएफटीए आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2008 से आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर बातचीत कर रहे हैं। समझौते में 14 अध्याय हैं।

इनमें वस्तुओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर), सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा शामिल हैं।

40 देशों के साथ 29 FTA

ईएफटीए के कनाडा, चिली, चीन, मैक्सिको और कोरिया सहित 40 भागीदार देशों के साथ 29 एफटीए हैं। मुक्त व्यापार समझौते के तहत, दो व्यापारिक साझेदार सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाएंगे।

इसके अलावा उनके बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को काफी कम या समाप्त कर देते हैं।

ईएफटीए देशों को भारत का निर्यात 2021-22 में 1.74 अरब डॉलर के मुकाबले 2022-23 के दौरान 1.92 अरब डॉलर रहा। वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल आयात 16.74 अरब डॉलर था, जबकि 2021-22 में यह 25.5 अरब डॉलर था।

दो महीने में 40 अरब डॉलर घटी एलन मस्क की दौलत, जानें रईसों की लिस्ट में पहले से तीसरे नंबर पर कैसे खिसके टेस्ला के मालिक

टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की दौलत 2024 के शुरुआती करीब ढाई महीनों में 40 अरब डॉलर घट गई है। वह सबसे रईसों की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। टॉप 10 में से किसी और भी अरबपति की दौलत इतनी तेजी से नहीं घटी है। मस्क की नेट वर्थ घटने की क्या वजह है? इस लिस्ट में अडाणी और अंबानी कहां हैं? आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। लेकिन, इस बार वह अपने बिजनेस में डाउनफॉल के चलते सुर्खियों में हैं।

इस साल यानी 2024 के शुरुआती करीब ढाई महीने में ही उनकी दौलत में 40 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट आ चुकी है। अगर टॉप 10 रईसों की लिस्ट देखें, तो इस दौरान बाकी किसी की संपत्ति इतनी तेजी से नहीं घटी।

यही वजह है कि जिस मस्क के सिर पर कभी दुनिया के सबसे रईस शख्स का ताज था, वह आज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स (Bloomberg Billionaire Index) के मुताबिक, शनिवार को मस्क की नेट वर्थ 189 अरब डॉलर थी।

रईसों की लिस्ट में अब टॉप पर कौन?

फिलहाल फ्रांसीसी लग्जरी फैशन कंपनी Louis Vuitton के फाउंडर बर्नार्ड अरनॉल्ट (Bernard Arnault) दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। उनकी नेट वर्थ 201 अरब डॉलर हैं। वहीं, ईकॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस (Amazon founder Jeff Bezos) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, 198 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ। बेजोस इस हफ्ते की शुरुआत में मस्क को पीछे छोड़कर सबसे रईस बने थे, लेकिन अब अरनॉल्ट उनसे भी आगे निकल गए हैं।

अमीरों की लिस्ट में क्यों फिसले मस्क?

मस्क की रईसी का आधार है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर टेस्ला (Tesla)। इसमें मस्क की हिस्सेदारी 21 फीसदी है। लेकिन, पिछले कुछ समय से टेस्ला के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। इस साल अब तक कंपनी की नेट वैल्यू 29 फीसदी तक घट चुकी है। टेस्ला के लिए चीन बड़ा बाजार है। लेकिन, इस हफ्ते कंपनी ने बताया कि उसकी चीन बिक्री के आंकड़े काफी निराशाजनक रहे।

पीएम मोदी वाराणसी में करेंगे 28 किलोमीटर लंबा रोड शो, कितने बजे पहुंचेंगे काशी, जानें

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन को ध्यान में रखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार रात्रि में एसपीजी द्वारा प्रधानमंत्री के संभावित रूप का सुरक्षा जायजा लिया गया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 28 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार इतना लंबा रोड शो किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए एसपीजी द्वारा बरेका गेस्ट हाउस और एयरपोर्ट पर एसपीजी के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम तैनात की गई है।

16 जगह किया जाएगा प्रधानमंत्री का स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार द्वारा शहर के लिए प्रस्थान करेंगे। 28 किलोमीटर रूट पर हर 500 मीटर पर काशी की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैदिक मंत्रों के साथ स्वागत किया जाएगा।

हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। जिन 16 पॉइंट का चयन किया गया है उन पॉइंट पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। शुक्रवार रात से ही वहां पर जवानों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए बाहर के जनपदों से भी फोर्स को बुलाया गया है।

रात 8:00 बजे पहुंचेंगे वाराणसी एयरपोर्ट

बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से शनिवार की रात 8:00 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट के एप्रन पर प्रधानमंत्री का काशी आगमन पर पुष्प देकर स्वागत किया जाएगा।

वाराणसी एयरपोर्ट से बाहर निकालने के बाद मुख्य गेट के बाहर डमरू दल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। इसी तरह हरहुआ चौराहा, शिवपुर चौराहा, अर्दली बाजार समेत कुल 16 जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी की जा रही है।

नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि वाराणसी आगमन के दौरान प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन करने जा सकते हैं हालंकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है।

कल सुबह आजमगढ़ के लिए करेंगे प्रस्थान

रात में बरेगा गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद अगले दिन हेलीपैड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। आजमगढ़ में नवनिर्मित आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत कई अन्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

कुशीनगर दौरे पर 10 मार्च को आएंगे सीएम योगी, कृषि विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास,,,।

परिवहन विशेष न्यूज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को कुशीनगर में भगवान बुद्ध एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी प्रदेश के 49 ब्लॉकों में कृषि कल्याण केंद्र का लोकार्पण और आचार्य नरेंद्र डीयू विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा के नेताओं ने गैलेक्सी होटल में बैठक कर तैयारी को लेकर चर्चा की।

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से आस-पास के कई जिलों के किसानों को उन्नत खेती और युवाओं को कृषि शिक्षा तथा रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आगामी 10 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर के मैत्रेय परियोजना की भूमि पर महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे।

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री शाही ने कसया के एक होटल में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी बैठक में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि बैठक को सम्बोधित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी है कि हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 10 मार्च को कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। दिसंबर में भवन बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2026 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों और युवाओं को समर्पित कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे।

वहीं कृषि मंत्री शाही ने भाजपा नेता पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी पूरी ताकत और क्षमता से ऐसा माहौल बनाएं कि विपक्षी हताश और निराश हो जाएं तथा अबकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज पूरे देश को जाए।

वहीं सांसद विजय कुमार दूबे ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से कुशीनगर की जनता में काफी उत्साह का माहौल है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिलान्यास कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने सभी का स्वागत एवं आभार प्रकट कर सभी मण्डल अध्यक्ष और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी लोग अभी से जुट जाएं।

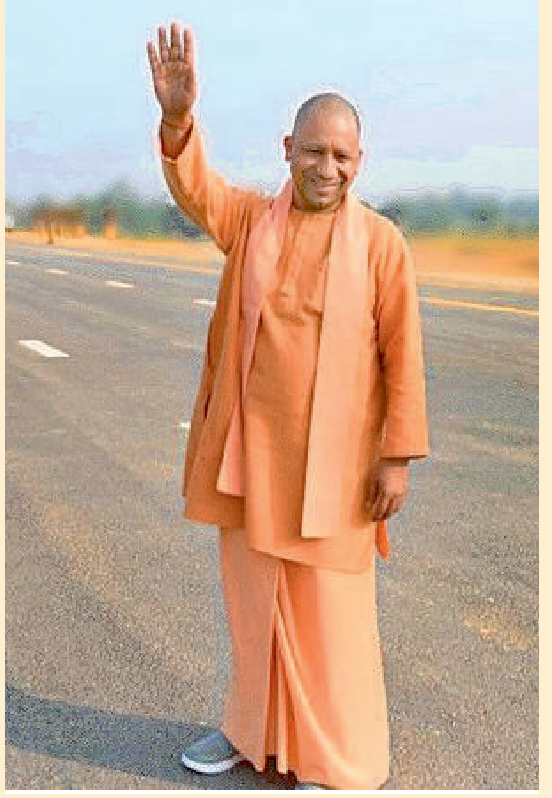

चार जिलों में सीएम योगी का दो दिवसीय दौरा, जौनपुर व चंदौली में करेंगे दौरा, पीएम मोदी के साथ जाएंगे रविवार को आजमगढ़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, और चंदौली कल शुक्रवार को ही पहुंचे हुए है। उन्होंने शुक्रवार को शिवरात्रि के पावन अवसर पर शाम को निकली हुई शिव बारात में भी शामिल हुए और पूरी बारात का अवलोकन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को जौनपुर और चंदौली में विकास, परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। साथ ही आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा, लोकार्पण और शिलान्यास समारोह की तैयारियों की जानकारी लेंगे। और काशी के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ भी साथ में जाएंगे।

बीजेपी चुनाव प्रभारी का बड़ा बयान, 'कोई समझौता नहीं होगा, सभी सीटों पर लड़ेगी बीजेपी'

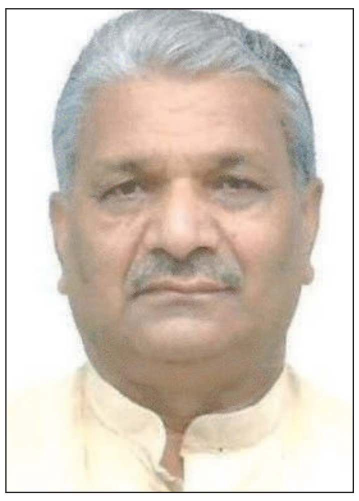

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वरः राज्य में बीजेपी-बीजेडी गठबंधन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन ने सामल मेंट को खारिज किया और अब एक और गठाबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर ने बीजेपी-बीजेडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर ने कहा, 'हमने चर्चा की है कि सभी सीटों पर कैसे लड़ना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी 80 से ज्यादा विधायक और 16 से ज्यादा सांसद जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उनसे पूछो जो गठाबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। टीम सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। हमारे पास पुरी और भुवनेश्वर के लिए उम्मीदवार हैं। संवित पात्रा पुरी से उम्मीदवार हैं और अपराजिता षाड़ंगी भुवनेश्वर से सांसद हैं। इसलिए सिर्फ ये दो सीटें ही नहीं बल्कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा।

मारू देवासी (राईका) समाज का वार्षिक सम्मेलन एवं महाशिवरात्रि पर्व धूम-धाम से मनाया

परिवहन विशेष न्यूज

बेंगलूरूः मारू देवासी (राईका) समाज महामंडल बेंगलुरू का 21वां वार्षिक सम्मेलन एवं महाशिवरात्रि महोत्सव कोतनूर स्थित महादेव मंदिर परिसर में सम्पन्न हुआ। शनिवार को सुबह 9 बजे पूजा-अर्चना के पश्चात मंत्रोच्चारण से ध्वजारोहण कार्यक्रमआयोजित किया गया। रात्रि में सत्संग जागरण का आयोजन हुआ। भजन गायक कैलाश पंवार गागुड़ा ने राजस्थानी मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। शनिवार को सुबह आम सभा आयोजित कार्यक्रम में मंदिर की वार्षिक पूजा-पाठ एंव अन्य बोलियां का समाज बन्धुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष सुजाराम मालावत ने भाषण स्वागत किया। सचिव रेवतराम भीम ने वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष गोरधनराम खटाणा ने आय व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। लाभार्थी परिवारों का एवं कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों का समाज की ओर से साफा माला द्वार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर महाप्रसादी की व्यवस्था की गई। जिसका समाज बंधुओ ने सपरिवार लाभ लिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष बद्रीराम गांगल एवं समस्त कार्यकारिणी महिला मंडल सहित समाज के अनेक गणमान्य मौजूद रहे।

अश्विनी वैष्णव बोले- पांच गुना बढ़कर 60 अरब डॉलर पहुंचेगा मोबाइल निर्यात, मिलेंगे 15 लाख रोजगार

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। देश में बने मोबाइल फोन की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत 50-60 अरब डॉलर तक के मूल्य का मोबाइल फोन निर्यात करेगा। यह आंकड़ा पिछले साल के 11 अरब डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात की तुलना में पांच गुना से अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोबाइल फोन निर्यात बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 15 लाख अवसर पैदा होंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिनकी संख्या बढ़कर 25 लाख पहुंचने की उम्मीद है। वैष्णव ने एक कार्यक्रम में कहा, 10 साल पहले भारत 98 फीसदी मोबाइल फोन आयात करता था। अब 99 फीसदी मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं। इसमें मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र पर जोर देने के साथ मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन देने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

2013 तक नाजुक अर्थव्यवस्था था भारत अब बन गया दुनिया का विकास इंजन

2013 तक दुनियाभर में भारत को लेकर

नकारात्मक चर्चा होती थी। हर कोई कहता था...यह नाजुक अर्थव्यवस्था है। चारों ओर अनिश्चितता है। लेकिन, आज का भारत बदल गया है। जब आप भारत को कहीं भी देखते हैं तो हर कोई कहता है कि यह पूरी दुनिया का विकास इंजन बन गया है। -अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री

दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना भारत

देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने एक दशक पहले तय किया गया लक्ष्य सफलता से पूरा कर लिया है। भारत ने इन 10 वर्षों में 4.1 लाख करोड़ रुपये के कुल 245 करोड़ मोबाइल फोन बनाए हैं। इसके साथ ही, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के मुताबिक, यह क्षेत्र 2014 में जहां 78 फीसदी आयात पर निर्भर था, अब यह 97 फीसदी तक आत्मनिर्भर हो गया है। उस समय उद्योग ने अगले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन उत्पादन का लक्ष्य तय किया था। आज 19.45 लाख करोड़ रुपये के कुल मोबाइल उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है।आईसीईए के मुताबिक, 2014-15 में भारत सिर्फ 1,556 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात करता था। 2023-24 में यह आंकड़ा 1.2 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है, जो 7,500 फीसदी वृद्धि दर्शाता है। 2014-24 के दौरान मोबाइल फोन निर्यात बढ़कर 3.22 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।

नीति आयोग का डिजिटल बुनियादी ढांचा मंच शुरू

उधर, वैष्णव ने बृहस्पतिवार को नीति आयोग के मंच 'नीति फॉर स्टेट्स' की शुरुआत की। यह नीति और शासन के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। साथ ही, मंत्री ने नीति आयोग की इमारत में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का भी उद्घाटन किया। नीति फॉर स्टेट्स मंच पर उपलब्ध सूचनाएं 10 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनमें कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका व कौशल, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी मामले, जल संसाधन और स्वच्छता शामिल हैं।

लद्दाख में आर्टिकल 371 हो सकती है लागू?

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। केन्द्र की मोदी सरकार लद्दाख में संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों को लागू कर सकती है।अगस्त 2021 में अनुच्छेद 370 के निरस्त्रीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था।जिसमें एक जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। बता दे कि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। वहीं स्थानीय लोग पूर्वोत्तर राज्यों की तरह संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को राज्य का दर्जा और आदिवासी दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं।इसके अलावा ,स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीट की मांग भी की जा रही है।लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ हाल में ही एक बैठक की ,जिसमें उन्होंने क्षेत्र में अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा बढाने की पेशकश की थी। आखिर अनुच्छेद 371 है क्या?

अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व देने के लिए और इन समूह को राज्य और केन्द्र सरकारों के हस्ताक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्ता का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लेह एपेक्स बॉडी(एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलाईंस (केडीए) से कहा है कि नौकरियों ,जमीन,और संस्कृति से संबंधित उनकी चिंताओ का ध्यान रखा जाएगा ।लेकिन सरकार लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं करेगी ।अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान लद्दाख की स्थानीय आबादी को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देगें। उल्लेखनीय है कि संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकारी खर्च की जरूरत का

आंकलन करने के लिए विकास बोर्ड के निर्माण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिए अनुच्छेद 371 के तहत अन्य राज्यों से संबंधित क्लॉज को बाद में संशोधनों के जरिए शामिल किया गया।

इसी तरह अनुच्छेद 371-एक के तहत नगालैंड के लिए विशेष प्रावधान शामिल है ।बतादें कि संसदीय ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागाओ की सामाजिक, धार्मिक या प्रथागत कानूनी प्रथाओ या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के हस्तांतरण और स्वामित्व को प्रभावित करते हैं ।अनुच्छेद-371-जी के तहत मिजोरम के मिजोवासियो को भी इसी तरह की सुरक्षा प्रदान की गई है।

वहीं अनुच्छेद 371-बी और सी असम और मणिपुर की विधानसभाओ में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं ।इन समितियों में क्रमशः आदिवासी क्षेत्रों और पहाडी क्षेत्रो से चुने गए विधायक शामिल होते है। इसी तरह सिक्किम विधान सभा में अनुच्छेद-371एफ के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान भी पेश किए गए है।

उल्लेखनीय है इससे पहले राज्यों के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद लागू हुए थे प्रावधान इनमें नगालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश (371-एच) और गोवा(371-आई) के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान है। इनमें से प्रत्येक राज्य के आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आने के तुरंत बाद पेश किए गए थे। अगर लद्दाख के लिए विशेष प्रावधान पेश किए जाते हैं तो यह पहली बार होगा जब उन्हें किसी राज्य के बजाय केन्द्र शासित प्रदेश के लि ए इन्हें पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार पहाडी परिषद के माध्यम से स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करेगी ।और सार्वजनिक रोजगार में 80 % प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार है।

खराब सोने के तरीके बन सकती है दिनभर थकान और आलस का कारण, इस तरह से पूरी करें नींद

स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह भोजन, योग और व्यायाम जरूरी है, उसी तरह पर्याप्त नींद भी जरूरी है। आमतौर पर हर व्यक्ति को रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को इसके बाद भी नींद की जरूरत होती है। इसके बाद भी उन्हें नींद आ जाती है और अगर उन्हें नींद नहीं आती तो वे दिन भर आलसी और थके हुए रहते हैं। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की नींद की जरूरत अलग-अलग होती है। आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि आपको कितनी नींद की जरूरत है. इसके लिए जब आप सुबह उठें तो इस बात पर ध्यान दें कि छह या सात घंटे की नींद के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आप आलस और थकान महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है. ऐसे में आपको अधिक नींद की जरूरत होती है और आप इसे बढ़ाकर आठ से नौ घंटे तक कर सकते हैं। इससे आपकी नींद जरूर पूरी होगी. आइए जानते हैं नींद की कमी के लक्षण और इसे पूरा करने के कुछ उपाय के बारे में-

नींद की कमी के लक्षण

दिन भर आलस्य और थकान महसूस होना।
दिन भर जम्हाई लेना।
बेचैनी महसूस हो रही है.
दिन में भी नींद आती रहती है.
काम पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता.
किसी भी काम में मन नहीं लगता.
हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस होना.
अधिक भूख लगना।
जागते रहने के लिए बार-बार चाय या कॉफी पर निर्भर रहना।
अलार्म बजने पर ही जागना।

पर्याप्त नींद लेने के उपाय

रात को सोने से पहले अपने हाथ-पैरों को अच्छी तरह साफ कर लें। हो सके तो नहा लें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी.

कुछ हल्का संगीत या गाने सुनें।

रात को सोने से पहले दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल दें और पंद्रह मिनट तक ध्यान करें।

हमेशा स्वस्थ और पौष्टिक आहार योजना का पालन करें।

अस्वस्थ जीवनशैली हमेशा समस्याओं का कारण बनती है।

इसलिए हेल्दी खाना ही खाएं.

अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो खुद मसाज करें। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी

ध्यान और योग भी आपको बेहतर नींद दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको सोने से पहले

कुछ देर योग और ध्यान करके खुद को पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कराना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023